

40 खातों में 106 करोड़ ‘जाति’ के हिसाब से थारेट

- धर्मांतरण मामले में फूट रहा है छांगुर बाबा का तिलिस्म

लखनऊ (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश एंटी टेरिस्ट स्क्वाड और प्रवर्तन निदेशालय ने धर्मांतरण गिरोह के सरगना जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा पर शिकंजा कस दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। ईंडी की जांच में सामने आया कि बाबा और उसके साथियों के पास 40 से अधिक बैंक खातों में 106 करोड़ रुपये से अधिक की रकम थी, जिनमें से अधिकांश पैसा पश्चिम एशिया से आया हुआ बताया गया है। छांगुर बाबा का असली नाम जमालुद्दीन है। यूपी के बलरामपुर के रेह्रा



माफ़ी गांव का निवासी है। कभी छोटे स्तर पर रत्न बेचने वाला यह शख्स मुंबई के हाजी अली दरगाह जाता था और वहीं से उसका आध्यात्मिक सफर शुरू हुआ। धीरे-धीरे वह खुद को रूहानी बाबा बनाने लगा। 2020 के बाद छांगुर बाबा की आर्थिक स्थिति अचानक बदल गई। रिपोर्ट्स के अनुसार, उन्होंने कथित रूप से अपने चमत्कारी इलाज और दुआओं से हजारों लोगों को अपने प्रभाव में लिया और धीरे-धीरे 3,000 से 4,000 गैर-मुस्लिमों का धर्मांतरण कराया, जिनमें से 1,500 से ज्यादा महिलाएं थीं। धार्मिक प्रवचन, इलाज, और आश्चर्यजनक चमत्कारों के नाम पर लोगों को आकर्षित किया जाता था। फिर धीरे-धीरे उन्हें मानसिक रूप से प्रभावित कर इस्लाम स्वीकार करने के लिए कहा जाता था।

शहीद पायलट ऋषिराज सिंह का अंतिम संस्कार

- फफक-फफक कर रोने लगे पिता छोटे भाई ने दी मुखाग्नि

पाली (एजेंसी)। चुरू में जुआर फाइटर जेट क्रैश में शहीद हुए फ्लाइट लेफ्टिनेंट ऋषिराज सिंह देवड़ा (23) का पैतृक गांव में सैन्य सम्मान से अंतिम संस्कार किया गया। छोटे भाई युवराज सिंह ने उनको मुखाग्नि दी। शहीद के अंतिम संस्कार के दौरान पिता जसवंत सिंह भावुक हो गए और रोने



लगे। वायुसेना के जवानों ने शहीद ऋषिराज सिंह को गाड़ ऑफ ऑन देकर आखिरी सलामी दी। इससे पहले पैतृक गांव में शहीद की तिरंगा यात्रा निकाली गई। आगे वायुसेना के जवान पीछे गांव वाले भारत की माता की जय और ऋषिराज अमर रहे के नारे लगाते हुए चले। शहीद की पार्थिव देह शाम करीब 6.10 बजे पैतृक गांव खिवांदा (पाली) लाई गई। शहीद के अंतिम दर्शन के लिए घर के आंगन में पार्थिव देह को रखा गया, जहां परिजनों और आसपास के गांवों से आए लोगों ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।

खट्टर के ड्रीम प्रोजेक्ट से हरियाणा सरकार का किनारा

- वज मंत्री बोले-केंद्र सरकार की मदद के बिना है मुश्किल

चंडीगढ़ (एजेंसी)। साढ़े 9 साल तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर के ड्रीम प्रोजेक्ट पर हरियाणा की नायब सरकार बैकफुट पर दिख रही है। ये ड्रीम प्रोजेक्ट अरावली की पहाड़ियों में 10 हजार एकड़ में बनने वाली दुनिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी का है। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए केंद्रीय मंत्री खट्टर लगातार



सक्रिय हैं। हाल ही में उन्होंने सीएम नायब सैनी और वन एवं पर्यावरण मंत्री राव नरबीर के साथ गुजरात के वनतारा का दौरा किया। इससे पहले साल 2022 में मुख्यमंत्री रहते वह शारजाह (दुबई) सफाई के दौरे पर गए थे। तब उनके साथ केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव थे। गुजरात के वनतारा दौरे के बाद हरियाणा सरकार अब इस प्रोजेक्ट को लेकर बैकफुट पर नजर आ रही है। इसकी बड़ी वजह जंगल सफारी बनाने और फिर उसके संचालन के लिए हर महीने खर्च होने वाला मोटा फंड है।

हर-हर महादेव के जयकारों से गूंज उठे शिवालय



नई दिल्ली (एजेंसी)। शुक्रवार को सावन का पहला दिन रहा। इसके चलते देशभर के शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ का विशेष श्रृंगार किया गया। वहीं,

फूलों से सजे मंदिर, वाराणसी से उज्जैन तक भारी भीड़

उज्जैन बाबा महाकाल का पंचामृत अभिषेक हुआ। हिंदू धर्म में सावन महीने का विशेष महत्व है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा समाप्त होने के साथ ही 11 जुलाई से सावन के महीने की शुरुआत हो गई। ऐसे में मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। लोग भार



से ही मंदिरों में लंबी लाइन लगाए हुए दिखे। इसके साथ ही मंदिरों को फूलों से सजाया गया। लोग पूजा-अर्चना के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं। दिल्ली, वाराणसी, हरिद्वार,

उज्जैन, अयोध्या के साथ-साथ तमाम शहरों में लोग भोले बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंचे। इस बार सावन का महीना 29 दिन का होगा और ये 11 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक

रेगा। इस बार सावन में 4 सोमवार पड़ेंगे- पहला 14 जुलाई, दूसरा 21 जुलाई, तीसरा 28 जुलाई और चौथा 4 अगस्त। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक, सावन महीने में ही भगवान शिव ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया था।

ऐसे में सावन की शुरुआत से ही मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है, जो पूरे महीने जारी रहने वाली है। सावन के चारों सोमवार को श्रद्धा और नियम के साथ पूजा करने पर भगवान शिव सभी कठिनाइयों को हर लेते हैं, ऐसी सोच के साथ श्रद्धालु भोले बाबा पर जल चढ़ाने पहुंचते हैं। हर सोमवार भगवान शिव को विशेष रूप से अलग-अलग वस्तुओं का अर्पण करने से जीवन के दोष, कष्ट और बाधाएं दूर होती हैं। इसी श्रद्धा के साथ भक्त भोलेनाथ के दर्शन करने पहुंचते हैं।

सिंधु पर भारत के ‘प्लान’ से दहशत में पाकिस्तान

चिनाब नदी पर वचार बांध परियोजना को गति देने की है तैयारी

इस्लामाबाद (एजेंसी)। सिंधु जल समझौते पर रोक के बाद से ही पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। इस बीच भारत ने एक नया प्लान तैयार कर लिया है, जो पाकिस्तान की नींद उड़ा देगा। भारत सरकार जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में चिनाब नदी पर एक



बुरी तरह फंसी शहबाज सरकार बढ़ जाएगी पाकिस्तान की टेंशन

महत्वपूर्ण जलविद्युत परियोजना क्वार बांध के निर्माण में तेजी लाने जा रही है। इसके लिए 3119 करोड़ रुपये के कर्ज की मांग की गई है। एक रिपोर्ट में इस बारे में जानकारी दी गई है। भारत ने ये कदम सिंधु जल संधि को स्थगित करने के फैसले के बाद उठाया है, जिससे पाकिस्तान में नदी के निचले इलाके में पड़ने वाले असर को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। इसी साल 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के एक दिन बाद भारत सरकार ने 1960 से चली आ रही सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया था। इस संधि के

तहत भारतीय क्षेत्र से होकर बहने वाली छह नदियों में से तीन का पानी पाकिस्तान को मिलता है। भारत ने कहा था कि जब तक पाकिस्तान भारतीय क्षेत्र में आतंकवाद को फैलाना बंद नहीं करता, संधि स्थगित रहेगी। पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के प्रॉक्सि द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली थी। हमले के कुछ दिन पहले ही

पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर ने पाकिस्तान में दिए गए एक संबोधन में कश्मीर को पाकिस्तान के गले की नस बताया था। मुनीर ने जिन्ना के द्विपक्ष सिद्धांत का जिक्र करते हुए कहा था कि हिंदू और मुसलमान को दो अलग कौम आतंकी हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के प्रॉक्सि द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली थी। हमले के कुछ दिन पहले ही

एक फोटो दिखाएं जिसमें भारत का नुकसान नजर आए

चेन्नई (एजेंसी)। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने शुक्रवार को ऑपरेशन सिंदूर पर पहली बार बयान दिया। उन्होंने कहा कि कई विदेशी मीडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत की कार्रवाई पर सवाल उठाए। भारत को नुकसान की खबरें चलाईं। उन्होंने कहा

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोले- हमने 9 आतंकी ठिकाने उड़ाए

कि विदेश मीडिया कोई भी फोटो या सैटेलाइट इमेज नहीं दिखा पाया। ना यह बता पाया कि नुकसान क्या हुआ। डोभाल ने यह बात शुक्रवार को आईआईटी मद्रास के 62वें दीक्षांत समारोह में कही। एनएसए ने कहा- वे कहते रहे कि पाकिस्तान ने ये किया, वो किया लेकिन मुझे एक फोटो दिखाइए जिसमें

ऑपरेशन सिंदूर पर पहली बार बोले एनएसए अजीत डोभाल

भारत का नुकसान नजर आए। यहां तक कि एक शीशा भी टूटा हो। हमसे कोई चूक नहीं हुई। हम उस पॉइंट तक सटीक थे जहां हमें पता था कि कौन कहां है। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ था। आतंकीयों ने 26 टूरिस्ट्स की हत्या कर दी थी।



इसके जवाब में भारत ने 7 मई को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों पर एयरस्ट्राइक की थी। इस दौरान सेना ने 100 आतंकी मार

गिराए थे। दोनों देशों के बीच 10 मई की शाम 5 बजे से सीजफायर पर सहमति बनी थी। डोभाल ने कहा, टेक्नोलॉजी और वॉरफेयर के बीच संबंध हमेशा महत्वपूर्ण होता है। हमें ऑपरेशन सिंदूर पर नाज है। हमें गर्व है कि इस दौरान हमने स्वदेशी तकनीक इस्तेमाल की। हमने सीमापार नौ पाकिस्तानी ठिकानों पर हमले का फैसला किया था। इनमें एक भी ठिकाना बॉर्डर के पास नहीं था। हमारे सभी निशाने सटीक थे। हमने सिर्फ आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया। उन्होंने

कहा, आप एक ऐसे देश, एक ऐसी सभ्यता से ताल्लुक रखते हैं, जो हजार सालों से संकटग्रस्त और लहलुहा न रही है। हमारे पूर्वजों ने बहुत कुछ सह है। मुझे नहीं पता कि राष्ट्र की इस धारणा को जिंदा रखने के लिए उन्होंने कितना अपमान और तकलीफ सहनी होगी। राष्ट्र, राज्य से अलग होता है। भारत एक राष्ट्र के रूप में हजारों सालों से अस्तित्व में है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के कई एयरबेस पर हमले किए हैं। इसमें एयरबेस के रनवे, हैंगर और इमारतों को नुकसान पहुंचा था। इनमें सरगोधा, नूर खान (चकलाला), भोलारी, जैकोबाबाद, सुक्कुर और रहीम यार खान एयरबेस शामिल हैं। एयरबेस पर हुए नुकसान की हाई क्वालिटी सैटेलाइट तस्वीरें 14 मई को सामने आई थीं। एयर मार्शल एके भारती ने 12 मई को बताया था कि भारत ने पाकिस्तान के अंदर चुनिंदा मिलिट्री टारगेट को निशाना बनाया था।

बीजेपी ने गैर मराठा वोटों को साधने की शुरु की कोशिश

मराठा-पेशवा पॉलिटिक्स से महाराष्ट्र में ‘खेला’ की तैयारी

मुंबई (एजेंसी)। महाराष्ट्र में मराठा पॉलिटिक्स के साथ पेशवा पर राजनीति शुरू हो गई है। खासकर 4 जुलाई के बाद से, जब गृह मंत्री अमित शाह ने खडकवासला स्थित



अपने पक्ष में एकजुट करने में जुटी पार्टी, विपक्ष भी तैयार

नेशनल डिफेंस अकैडमी में पेशवा बाजीराव प्रथम की प्रतिमा का अनावरण किया है। इसके पहले बीजेपी की राज्यसभा सांसद मेधा कुलकर्णी ने पुणे स्टेशन का नाम बदलकर पेशवा बाजीराव प्रथम के

नाम पर रखने की मांग की थी। यह माना जा रहा है कि बीजेपी ने गैर मराठा वोटों को अपने पक्ष में एकजुट करने के लिए बाजीराव पेशवा को पहचान दी जा रही है। अमित शाह के कार्यक्रम के बाद पेशवा के विरासत पर भी बहस छिड़ गई है। दरअसल महाराष्ट्र में 32 प्रतिशत मराठे हैं, जो करीब 150 विधानसभा सीटों पर

प्रभावशाली हैं। राज्य में बने 18 मुख्यमंत्रियों में से 10 मराठे हैं। इसके अलावा राज्य की राजनीति में ब्राह्मण नेताओं ने भी बड़ा कद हासिल किया है। वहां दशकों से मराठा और ब्राह्मणों के बीच राजनीतिक वर्चस्व मुद्दा रहा है। राजनीतिक तौर पर नायकों के चुनाव में इसका असर रहा। शिवाजी महाराज हिंदुत्व के प्रतीक बन गए।

ओडिशा में 40 हजार से ज्यादा महिलाएं हो गई हैं गायब:राहुल

भुवनेश्वर में गरजे कांग्रेस नेता, बीजेपी सरकार पर किया बड़ा प्रहार

भुवनेश्वर (एजेंसी)। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को भुवनेश्वर के बारामुंडा रैली ‘सविधान बचाओ समावेश’ को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि ओडिशा में 40,000 से ज्यादा महिलाएं गायब हो गई हैं। आज तक नहीं मालूम कि ये महिलाएं कहां पर गईं। महिलाओं के खिलाफ हर रोज यहां पर अत्याचार होता है। यहां की सरकार को इससे कोई लेना-देना नहीं है। राहुल गांधी ने कहा, ‘ओडिशा सरकार का एक ही काम है कि राज्य के गरीब लोगों के हाथों से ओडिशा का धन चुराना। पहले बीजेडी सरकार ने यही किया और अब

बीजेपी सरकार यही कर रही है। एक तरफ ओडिशा की गरीब जनता, दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, मैदान में एक विशाल रैली ‘सविधान बचाओ समावेश’ को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि ओडिशा में 40,000 से ज्यादा महिलाएं गायब हो गई हैं। आज तक नहीं मालूम कि ये महिलाएं कहां पर गईं। महिलाओं के खिलाफ हर रोज यहां पर अत्याचार होता है। यहां की सरकार को इससे कोई लेना-देना नहीं है। राहुल गांधी ने कहा, ‘ओडिशा सरकार का एक ही काम है कि राज्य के गरीब लोगों के हाथों से ओडिशा का धन चुराना। पहले बीजेडी सरकार ने यही किया और अब



‘बीजेपी लगातार सविधान पर आक्रमण कर रही है। जिस तरह से महाराष्ट्र में चुनाव चोरी किया गया, उसी तरह से बिहार में चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। चुनाव चोरी करने के लिए चुनाव आयोग ने नई साजिश शुरू की है।

अलग-अलग हादसों में दो की मौत

इंदौर। शहर में अलग-अलग हादसों में दो लोगों की मौत हो गई। पहला मामला एरोड्रम और दूसरा मामला शिप्रा थाना क्षेत्र का है। एरोड्रम पुलिस के मुताबिक घटना सुपर कॉरिडोर पर टीसीएस कंपनी के सामने की है। मृतक का नाम शैलेन्द्र है। वह बाइक से गांधीनगर तरफ जा रहा था, तभी सुपर कारीडोर पर तेज गति से आ रहे अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी थी। हादसे में युवक की मौके पर मौत हो गई थी। शिप्रा पुलिस ने बताया कि ग्राम पीर कराड़िया में 21 जून को बाइक की टक्कर से घायल महिला की मौत हो गई। मृतका का नाम संगीता बाई पति शिवनारायण पटेल निवासी डकाच्या है। बाइक नंबर एमपी 09 क्यूटी 5044 के चालक सचिन पटेल निवासी ग्राम डकाच्या पर कंस दर्ज किया है। घटना दिनांक को आरोपी बाइक चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिया था, जिससे पीछे चल रही संगीता बाई की बाइक टकरा गई थी। हादसे में महिला को गंभीर चोट आई थी।

परिवार अमरनाथ गया, घर में घुसे चोर

इंदौर। परिवार अमरनाथ यात्रा पर गया था, जब वापस लौटा तो मुख्य दरवाजे के ताले टूटे मिले। चोर सुने घर से एक सोने की चेन वजनी 20 ग्राम, मंदिर में रखी तीन चांदी की मूर्तियां श्रीगणेश, लक्ष्मीजी और सरस्वतीजी की, 30 चांदी के सिक्के, 3 घड़ियां तथा नकदी रुपए ले गए। जूनी इंदौर पुलिस को प्रेम नगर निवासी शिवसहाय पांडे ने बताया कि वे 30 जून को परिवार सहित अमरनाथ यात्रा पर गए थे।

जिला संयोजक को धमकाने वाला गिरफ्तार

इंदौर। कर्बला मैदान पर हनुमान जी की आरती के दौरान विधिप के जिला संयोजक सुमित ढांडिया को सोशल मीडिया पर धमकी मिली थी। इसमें लिखा था कि इसकी गर्दन कौन उतारेगा! इसके बाद सुमित अपने साथियों के साथ जूनी इंदौर थाने पहुंचे और युवक के खिलाफ केस दर्ज कराया। मामले में पुलिस ने आरोपी सुफियान अंसारी निवासी खजराना को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने पूछताछ के बाद अपने कमेट्स को लेकर माफी भी मांगी है।

सेंट्रल जेल में अब बनेगा मसाला, मशीनें लगी

इंदौर। शहर की सेंट्रल जेल में बंद कैदियों को पुनर्वास को लेकर प्रशासन लगातार काम कर रहा है। इसी क्रम में आगामी दिनों में यहां 5 प्रकार के मसाले तैयार किए जाएंगे। मसाला तैयार करने मशीनें स्थापित हो चुकी है। शीघ्र ही कैदियों को प्रशिक्षण देकर इस उद्योग से जोड़ा जाएगा। जेल अधीक्षक अलका सोनकर ने बताया कि गुरु पूर्णिमा पर इस कार्य का शुभारंभ जेल महानिदेशक गोविंद प्रताप सिंह ने किया। प्रारंभिक तौर पर इस काम में 20 कैदियों की मदद ली जाएगी। यहां धनिया, गरम मसाला, कश्मीरी मिर्च, हरी मिर्च, हल्दी से मसाला तैयार होगा। तैयार मसाला जेल के आउटलेट पर भी तीन पैकिंगों में उपलब्ध रहेगा। इसका नाम मां अहिल्या मसाला उद्योग रखा गया है। प्रदेश में यह पहली जेल है, जहां मसाला तैयार किया जाएगा। खिलौना उद्योग भी लंबे समय से प्रस्तावित है, इसके लिए भी प्रशासन लगातार प्रयासरत है।

नाबालिग को सोशल मीडिया पर धमकाया

इंदौर। इंस्टाग्राम पर मूढ़ के युवक ने नाबालिग को धमकाया कि शादी नहीं की तो ठीक नहीं होगा। नाबालिग की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। पीड़िता के अनुसार, वह 3 साल पहले उसकी मूढ़ के युवक से शादी समारोह के दौरान पहचान हुई थी। युवक ने उसका मोबाइल नंबर लिया और फिर इंस्टाग्राम पर फ्रेंड रिक्लेस्ट भेजी। कुछ समय तक दोनों की बात होती रही, लेकिन कुछ महीनों पहले युवक ने उससे बात करना बंद कर दी। एक दिन पहले जब वह सन्मति स्कूल के पास से जा रही थी, तभी युवक पीछे आया और बोला कि तू मुझसे बात क्यों नहीं करती! इंस्टाग्राम पर फिर से बात शुरू की जाए। जब लड़की ने मना किया तो उसने जान से मारने की धमकी दी। घबराई पीड़िता ने घर जाकर परिजनों को बताया। परिजन उसे थाने लेकर पहुंचे, जहां पुलिस ने छेड़छाड़ और धमकी का मामला दर्ज किया है।

बिना आईडी किराएदार रखने पर बवाल, पुलिस जांच में जुटी

बिना पुलिस सूचना 25 मजदूरों को किराए पर रखा

इंदौर। पश्चिम क्षेत्र के नागिन नगर के पास विजय श्री नगर में उस समय विवाद गहराया जब मकान मालिक राजू भाटी द्वारा बिना किसी आईडी प्रूफ और पुलिस सूचना के 25 मजदूरों को किराए पर रखने की जानकारी सामने आई। सभी मजदूर उत्तर प्रदेश से आए हैं और मेट्रो स्टेशन निर्माण में कार्यरत हैं। घटना की जानकारी रात करीब 11 बजे बजरंग दल के तंत्र शर्मा को स्थानीय निवासियों ने दी। उन्होंने बताया कि किराए पर रह रहे कुछ मजदूरों ने एक हिंदू मजदूर के साथ मारपीट की की है। सूचना पर बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और एरोड्रम थाना पुलिस को बुलाया। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए सभी किरायेदारों को थाने बुलाया और पूछताछ शुरू की। बजरंग दल के तंत्र शर्मा ने प्रशासन से मांग की है कि शहर में ऐसे सभी मकान मालिकों पर कड़ी कार्रवाई की जाए,जो बिना पहचान पत्र और पुलिस सत्यापन के लोगों को किराए पर रखते हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पूर्व में राज नगर क्षेत्र में भी इसी तरह की लापरवाही हो चुकी है, लेकिन कोई कठोर कार्रवाई नहीं हुई। थाना प्रभारी तरुण भाटी ने आश्वासन दिया है कि सभी संदिग्धों की जांच की जा रही है और मकान मालिक के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस पूरे मामले को गंभीरता से जांच कर रही है।

अज्ञात कारणों से जहर खाया

इंदौर। अर्धेड़ महिला ने अज्ञात कारणों के चलते जहर खाकर आत्महत्या कर ली। विजयनगर थाना इलाके के न्यू अंजनी नगर में रहने वाली पार्वती पति राधेश्याम (52) ने की मौत हो गई। महिला ने जहर खाया था। वहीं अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र के महावर नगर निवासी शांति बाई पति रामनारायण ने एसिड पीकर जान दे दी। पुलिस ने दोनों मामलों में मर्ग कायम कर लिया है। इसी प्रकार, बाइक से ऑकरेश्वर जा रहे युवक की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। पुलिस के अनुसार, निपानिया निवासी संजय पिता बुद्धसेन (45) बुधवार को ऑकरेश्वर जाने के लिए निकला था। रास्ते मे सनावद के समीप वह बेसुध हालात में मिला था। राहगीरों ने परिजनों को इसकी जानकारी दी।

शिलांग जेल में बंद सोनम को सप्ताह में एक बार फोन करने की अनुमति

तीन बार बात कर चुकी, हत्या की साजिश का राज अभी रहस्य

इंदौर। चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में शिलांग जेल में बंद सोनम रघुवंशी को एक राहत मिली है। जेल प्रशासन ने उसे सप्ताह में एक बार अपने परिवार से फोन पर बात करने की अनुमति दी है। अब तक वह तीन बार अपने परिवार से फोन पर बात कर चुकी है। हालांकि, उसने अपने भाई गोविंद रघुवंशी से बात की है या नहीं, इस बात की पुष्टि अभी नहीं हो सकी। राजा की हत्या 23 मई को शिलांग में की गई थी, जब वह पत्नी सोनम के साथ हनीमून पर गया था।हत्या



के पीछे सोनम उसके प्रेमी राज कुशवाह और उसके दो दोस्तों का हाथ बताया जा रहा है। इस मामले में सोनम के अलावा राज कुशवाह, विशाल चौहान, आनंद कुर्मी और आकाश राजपूत को गिरफ्तार कर शिलांग जेल भेजा गया है। उधर, सोनम के भाई गोविंद ने कहा कि वे पुलिस जांच पूरी होने के बाद शिलांग जाकर सोनम से मिलेंगे और फिर तय करेंगे कि कानूनी मदद ली जाए

इंदौर में संपत्तियों के जीआईएस सर्वे के लिए निगम को 7.25 % पर एजेंसी मिली

एजेंसी को यह राशि नई संपत्तियों से मिलने वाले संपत्ति-कर पर मिलेगी

इंदौर। नगर निगम ने एक बार फिर शहर में संपत्ति कर के जरिए अपनी कमाई बढ़ाने के लिए जीआईएस सर्वे कराने का फैसला किया। नगर निगम द्वारा जारी किए गए टेंडर के जवाब में तीन फर्मों ने यह काम करने में रुचि दिखाई थी। इस टेंडर में न्यूनतम ऑफर के कारण निगम ने झारखंड की फर्म ‘स्पैरो’ का चयन किया है। इस फर्म को यह सर्वे करने का काम सौंपने का प्रस्ताव तैयार कर मंजूरी के लिए महापौर परिषद को भेजा गया। इस फर्म ने नगर निगम को ऑफर दिया कि हमारे द्वारा किए जाने वाले सर्वे से निगम की कमाई में जो इजाफा होगा, उस राशि में से 7.25 प्रतिशत राशि हमें दी जाए। इस कंपनी का यह ऑफर निगम को पसंद आया। निगम ने इसे मंजूरी देने के लिए आगे बढ़ा दिया है। इसमें यह स्पष्ट कर दिया गया कि नगर निगम को संपत्ति कर से होने वाली कुल आय में से यह राशि नहीं दी जाएगी। बल्कि, पूर्व में निगम को जो आय होती थी, उसे घटाकर जो नई आय होगी, उस नई आय की कुल राशि पर से 7.25 प्रतिशत के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। इस एजेंसी ने राजस्थान के कई शहरों में इस तरह का सर्वेक्षण कार्य किया है। अभी भी इस एजेंसी का कई शहरों में इस तरह का काम चल रहा है।

7 लाख पंजीकृत संपत्ति करदाता – नगर निगम के पास संपत्ति कर देने के लिए पूरी निगम सीमा में 7 लाख पंजीकृत संपत्ति है। इस एजेंसी द्वारा



इन सभी संपत्ति का सर्वे किया जाएगा और यह देखा जाएगा कि उनके द्वारा बराबर ईमानदारी से टैक्स दिया जा रहा है अथवा नहीं। इसमें खासतौर पर जो संपत्ति पंजीकृत है, उसमें संपत्ति मालिक द्वारा जितने निर्मित क्षेत्र का टैक्स दिया जा रहा है, इसका परीक्षण इस एजेंसी द्वारा किया जाएगा। इस परीक्षण में इस बात पर फोकस किया जाएगा कि कुल निर्मित क्षेत्र कितना है, उसमें से सीमेंट का पक्का कितना है, शेड डाला हुआ कच्चा हिस्सा कितना है और इनमें से

किस निर्माण का टैक्स दिया जा रहा है अथवा नहीं दिया जा रहा।

यह एजेंसी नई ढूंढने का काम करेगी– इस सर्वे में एजेंसी द्वारा उन संपत्तियों को भी ढूंढा जाएगा, जो नगर निगम को संपत्ति कर नहीं दे रहे हैं। इसमें खासतौर पर ऐसी संपत्ति शामिल होती है, जो प्लाट या खुली जमीन के रूप में है और उसके स्वामी द्वारा उसका टैक्स नहीं चुकाया जा रहा है। ऐसी संपत्तियों को ढूंढने के बाद में उनका नगर निगम में संपत्ति कर का खाता खोलकर

एमपी बोर्ड 10वीं-12वीं पूरक परीक्षा परिणाम जुलाई के अंत तक संभव

20 जुलाई तक मूल्यांकन कार्य, कॉलेज एडमिशन प्रक्रिया शुरू

इंदौर। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (एमपीबीएसई) द्वारा 10वीं और 12वीं की पूरक परीक्षाओं का परिणाम जुलाई के अंतिम सप्ताह या अगस्त की शुरुआत में जारी किया जा सकता है। बोर्ड ने मूल्यांकन कार्य को अंतिम रूप देने की तैयारियां पूरी कर ली हैं। जानकारी के अनुसार, इस वर्ष लगभग 3.3 लाख छात्र पूरक परीक्षाओं में शामिल हुए, जो 17 जून से 5 जुलाई तक आयोजित की गई थीं। मूल्यांकन दो चरणों में किया जा रहा है, जिसमें पहला चरण 11 जुलाई को समाप्त होगा और दूसरा चरण

12 से 20 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान लगभग 10 लाख उत्तरपुस्तिकाओं की जांच की जा रही है। एमपीबीएसई के मुख्य सिस्टम अधिकारी भूपेश गुप्ता ने बताया कि 20 जुलाई तक मूल्यांकन कार्य पूरा कर लिया जाएगा और इसके बाद परिणाम जारी कर दिए जाएंगे। हालांकि, परिणाम की देरी से कक्षा 12वीं के छात्रों को प्रवेश संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि, राज्य में कॉलेज एडमिशन प्रक्रिया अपने तीसरे चरण में पहुंच चुकी है। परिणाम में हो रही देरी से कई छात्र काउंसलिंग में शामिल नहीं हो पा रहे हैं और उन्हें सीटों से वंचित होने का खतरा है। बोर्ड ने छात्रों को आश्वास किया है कि समय पर रिजल्ट जारी करने के प्रयास तेजी से जारी हैं।

तेज बज रहा डीजे बंद करवाने पहुंचे प्रधान आरक्षक को शराबियों ने पीटा

इंदौर। बुधवार रात गुरु शंकर नगर में शराबियों ने जमकर उत्पात मचाया। युवती से छेड़छाड़-मारपीट की और पुलिसकर्मों को दौड़ा दौड़ाकर पीटा। डायल-100 की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की। पुलिस ने सात आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके विरुद्ध मारपीट, शासकीय कार्य में बाधा, तोड़फोड़, बलवा, छेड़छाड़ के तीन मुकदमे दर्ज किए। घटना रात करीब साढ़े 11 बजे लाल बार्डेंडी (गुरु शंकर नगर) की है। डायल-100 को सूचना मिली थी कि कुछ लोग तेज आवाज में डीजे बजा रहे हैं। 58 वर्षीय प्रधान आरक्षक मुन्नालाल मिश्रा चालक करण सिंह को लेकर मौके पर पहुंच गए। रात में शराबियों का एक झुंड आपस में विवाद कर रहा था। मुन्नालाल द्वारा अलग-अलग करने पर शराबी उन पर टूट पड़े। लंबे बाल और संफेद शर्ट वाले युवक ने मुन्नालाल को पकड़ा और लाल शर्ट वाले एक युवक ने पथर मारकर सिर फोड़ डाला। उनकी पूरी वर्दी खून से सन गई। घायल होने के बाद भी पीली शर्ट वाला युवक पाइप लेकर आया और मुन्नालाल को दौड़ा दौड़ाकर मारा।



लड़कियों का थाने में हंगामा

शहर के संयोगितागंज थाना क्षेत्र स्थित पारसी मोहल्ला में मंगलवार देर रात हंगामे की स्थिति बन गई जब पीजी में रहने वाली कुछ युवतियां नशे में धुत युवकों को छुड़ाने थाने पहुंचीं और पुलिसकर्मियों से बहस करने लगीं। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार, कृष्ण और कुलदीप नामक दो युवक देर रात पीजी में रहने वाली युवतियों से मिलने पहुंचे थे। दोनों युवक नशे में थे और मोहल्ले में आपतिजनक हरकत कर रहे थे। जब रहवासियों ने इसका विरोध किया तो युवकों ने उनसे झगड़ा कर मारपीट शुरू कर दी। सूचना मिलने पर संयोगितागंज पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को थाने ले आईं। थोड़ी ही देर बाद पीजी में रहने वाली युवतियां थाने पहुंचीं और पुलिस से बदसलूकी शुरू कर दी। वीडियो में युवतियां पुलिसकर्मियों से बहस करती, गाली-गलौज करती और वीडियो बना रहे एक पुलिसकर्मों को मारने की कोशिश करते हुए दिख रही हैं। एसीपी तुषार सिंह ने बताया कि पुलिस ने युवकों पर केस दर्ज कर लिया है और वीडियो व चरमदीदी के आधार पर उचित कार्रवाई की जा रही है।



नीले घने आसमान पर काले बादलों का डेरा।

फोटो- ऋतुराज बुड़ावनवाला,खाचरौद (उज्जैन)

उन पर टैक्स की लायबिलिटी निकाली जाएगी। इससे नगर निगम को इन संपत्तियों से स्थायी रूप से राजस्व संग्रहण का अवसर मिल जाएगा।

रोज 2000 संपत्तियों का सर्वेक्षण – इस एजेंसी को यह काम 1 साल यानी की 365 दिन में पूर्ण करना है। यदि नगर निगम में वर्तमान में मौजूद 7 लाख खातों पर भी यह एजेंसी जांच करने का काम करती है, तो एजेंसी को प्रतिदिन कम से कम 2000 संपत्ति का सर्वेक्षण करना होगा, तब जाकर एक महीने में करीब 60 हजार संपत्ति का सर्वेक्षण हो सकेगा। तभी यह एजेंसी एक साल में इस काम को पूरा कर सकेगी।

यह होता है जीआईएस – जीआईएस (ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम) का मतलब ‘भौगोलिक सूचना प्रणाली’ है। यह एक कंप्यूटर-आधारित प्रणाली है, जो भौगोलिक डेटा को एक्त्रित करने, संग्रहित करने, विश्लेषण करने, प्रबंधित करने और प्रदर्शित करने के लिए उपयोग की जाती है। जीआईएस एक ऐसा उपकरण है, जो नक्शों और डेटा का उपयोग करके बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। यह विभिन्न स्थानों के बारे में जानकारी एक्त्रित करने, उसका विश्लेषण करने और उसे प्रदर्शित करता है।

डीआरपी लाइन में पदस्थ बीमार हेड कांस्टेबल ने खुदकुशी की

पुलिस में दो माह में यह आत्महत्या की तीसरी घटना

इंदौर। एक साल से डीआरपी लाइन में पदस्थ हेड कांस्टेबल ने बीमारी के चलते ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। वे घर से सुबह 10 बजे कुछ देर में आने का बोलकर निकले थे, जब काफी देर तक घर नहीं पहुंचे, तो परिजनों ने पुलिस को शिकायत की। पुलिस ने उनकी गुमशुदगी दर्ज की, तभी करीब एक बजे राहगीर से सूचना मिली की रेलवे पटरी पर शव पड़ा है। जब पुलिस ने शव की शिनाख्त की तो वह पुलिसकर्मी जितेन्द्र चौहान की थी। लसुड़िया पुलिस के अनुसार घटना कैलाद हाला इलाके की है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि जितेंद्र चौहान पिछले दो साल से कैसर और शुगर की बीमारी से जूझ रहे थे। उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी। इससे वह मानसिक तनाव में रहते थे। जितेंद्र पहले सेंट्रल



कोतवाली थाने में पदस्थ थे और जावरा कपाउंड क्षेत्र में रहते थे। बाद में वह स्कीम नंबर 114 में शिफ्ट हो गए थे। कुछ समय पहले उनका तबादला जौन 2 में हुआ था और डीसीपी एसआईटी टीम में भी सेवा दी थी।

इसके बाद उनका ट्रांसफर कनाड़िया थाने में हुआ, लेकिन वहां वह केवल 10 दिन ही काम कर सके। बीमारी के चलते उन्होंने पुलिस लाइन में तबादला करा लिया था और छुट्टी पर चले गए थे। मृत हेड कांस्टेबल के तीन बच्चे हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

दो माह में तीसरी आत्महत्या

पुलिस विभाग में दो माह में यह तीसरी आत्महत्या है। इसके पहले परदेसीपुरा थाने में पदस्थ हेड कांस्टेबल विनोद यादव ने प्रेम प्रसंग के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। विनोद का 10 साल से युवती से संबंध था। इसके बाद द्राकपुुरी थाने में पदस्थ आरक्षक अनुराग भाभर ने सर्विस रायफल से खुद को गोली मार ली थी। अनुराग की आत्महत्या का कारण पता नहीं चल पाया है। यह तीसरी आत्महत्या है, जो बीमारी के चलते हुई।

पुल निर्माण में देरी पर नोटिस जारी

इंदौर। वार्ड 70 स्थित आदर्श इंदिरा नगर कॉलोनी और राजमोहल्ला के बीच प्रस्तावित पुल निर्माण देरी पर हार्डकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने मामले में निगम और ठेका लेने वाली कंपनी जेडीके कंसल्टेंसी सर्विसेस को नोटिस जारी किया है। जानकारी के मुताबिक, 30 जनवरी 2018 को निगम ने कंपनी को 1,09,36,100 रुपए में पुल निर्माण का कार्य अदेश दिया था, परंतु अब तक निर्माण शुरू नहीं हो पाया। इससे क्षेत्र की दो कॉलोनियों के बीच यातायात बाधित हुआ। निगम ने गत वर्षों में कंपनी को 26-4-2019, 3-9-2019, 28-11-2019, 2-1-2020, 22-12-2020 तथा 15-6-2022 को पत्र लिखकर चेताया भी था। यह भी अवागत कराया था कि पुल निर्माण नहीं होने से निगम की छवि धूमिल हो रही है। मामले में मनोज सिंह कुशवाह ने जन्हित याचिका दायर की थी। इसमें नगरीय प्रशासन विभाग, नगर निगम इंदौर, संभाग आयुक्त तथा कंपनी को पक्षकार बनाया है।

संपादकीय

भागवत का इशारा किस ओर?

राष्ट्रीय स्वयं सेवक के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने 75 की उम्र में रिटायरमेंट की बात कहकर नई अटकलों को जन्म दे दिया है। राजनीतिक हल्कों में इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि भागवत का यह इशारा किसके लिए है? क्या यह इसी साल जीवन के 75 साल पूरे करने वाले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लिए है या फिर खुद मोहन भागवत ने अपने भावी प्लान का संकेत दिया है, क्योंकि वो स्वयं भी इसी साल सितंबर में जीवन के 75 वसंत पूरे कर रहे हैं। या फिर ये संघ और भाजपा में काम कर रहे सभी लोगों के लिए है? अगर भागवत का बयान व्यक्तिशः किसी के लिए भी नहीं है तो फिर इस ‘जनरल स्टेटमेंट’ का क्या मतलब है? क्या संघ अब नरेन्द्र मोदी के उत्तराधिकारी की खोज में जुट गया है? गौरतलब है कि नागपुर में एक पुस्तक विमोचन समारोह में भागवत ने कहा कि पचहत्तर साल की उम्र के बाद रिटायर हो जाना चाहिए। वे संघ के दिवंगत कार्यकर्ता मोरोपंत पिंगले के जीवन और उनके योगदान की चर्चा कर रहे थे। भागवत ने पिंगले की निस्वार्थता, विनम्रता और राष्ट्र निर्माण के प्रति उनके समर्पण की प्रशंसा की। इसी संदर्भ में उन्होंने पिंगले के उस नजरिए का उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने 75 वर्ष की आयु को एक ऐसी सीमा के रूप में देखा, जहां व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारियों को दूसरों को सौंप देना चाहिए। भागवत ने इसे पिंगले की विनम्रता और अगली पीढ़ी को अवसर देने की उनकी सोच के रूप में पेश किया। भागवत ने कहा कि राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान उन्होंने धैर्य, विनम्रता और संघ के प्रति समर्पण का परिचय दिया। भागवत ने मोरोपंत पिंगले के जीवन पर आधारित पुस्तक मोरोपंत पिंगले: द आर्किटेक्ट ऑफ हिंदू रिसर्जेंस के लिए उद्धरण के साथ कहा कि मोरोपंत जी कहते थे कि पचहत्तर साल के बाद समझ लो कि अब रुक जाना चाहिए, तुम्हारी उम्र हो गई है। अब दूसरों को काम करने दो। भागवत ने जिस भी मंशा से यह कहा हो, लेकिन जल्द ही उसने राजनीतिक रंग ले लिया। इसका एक कारण यह है कि खुद भाजपा और संघ ने अपने कई पुराने और दिग्गज नेताओं को 75 के बैरियर के तहत मुख्य धारा से बाहर कर घर बिछा दिया। इनमें लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मोहनर को उज्जैन सिन्हा, सुमित्रा महाजन आदि प्रमुख हैं। कहने को जेठे मार्गदर्शन मंडल में भेजा गया, लेकिन उनसे किसी ने कोई मार्गदर्शन लिया हो, इसका कोई प्रमाण नहीं है। वैसे भी 75 में रिटायरमेंट का अघोषित नियम है, कोई लिखित संकल्प नहीं है। विपक्षी नेताओं, खासकर शिवसेना युबीटी के सांसद संजय राउत कि मोहन भागवत यह संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं। पीएम मोदी ने आडवाणी, जोशी जैसे नेताओं को 75 साल की उम्र में रिटायरमेंट के लिए मजबूर किया। क्या वे स्वयं इस नियम का पालन करेंगे? हालाँकि, पिछले साल मई में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ़ किया था कि बीजेपी के संविधान में 75 वर्ष की आयु में रिटायरमेंट का कोई औपचारिक नियम नहीं है। शाह ने यह भी कहा था कि मोदी 2029 तक देश का नेतृत्व करेंगे और वे अगले लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी का नेतृत्व करेंगे। वैसे भी मोदी पूरी तरह फिट हैं, ऐसे में केवल आयु की बिना पर वो कोई रिटायरमेंट लेगे या इसके बारे में सोचेंगे भी, इसकी संभावना नहीं के बराबर है। भाजपा और संघ अभी मोदी का कोई विकल्प भी तैयार नहीं पर पाया है। भागवत के बयान के बाद भाजपा और संघ में पीढ़ी परिवर्तन देखने को मिलता है या नहीं, यह देखने की बात है, लेकिन इससे उत्तराधिकार की लड़ाई तेज हो सकती है।

बिहार में चुनाव से पहले घोषणाओं का मानसून



नजरिया
सुनील कुमार महला

लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं।

बिहार में चुनाव से पहले राजनीतिक गलियारों में हलचल जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोतिहारी में दौरे पर आने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 18 जुलाई को मोतिहारी दौरे से पहले एनडीए ने राजद को बड़ा झटका दिया। मोतिहारी के लगभग 200 राजद मुस्लमान कार्यकर्ताओं को जदयू ने घर वापसी कराई गई। मोतिहारी के बंजरिया में आयोजित मिलन समारोह में जदयू के वरिष्ठ नेता और विधान पार्षद खालिद अन्वर की मौजूदगी में राजद के 200 मुस्लिम कार्यकर्ताओं ने जदयू की सदस्यता लेते हुए पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार पर भरोसा जताया। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी पेंशनधारकों के खातों में नई पेंशन राशि भेजी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने तय कर लिया है कि हर महीने 400 से 1100 रुपए मिलेंगे। यह राशि जून से लागू की गई है। हर महीने की 10 तारीख को पेंशन की राशि सभी के खाते में चली जाएगी।

हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला आरक्षण को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने यह घोषणा की है कि बिहार राज्य की मूल निवासी महिलाओं को अब राज्य की सभी सरकारी सेवाओं, संवर्गों और सभी स्तरों के पदों पर सीधी नियुक्ति में 35 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा तथा यह आरक्षण सभी प्रकार की सरकारी नौकरियों पर लागू होगा। पाठकों को बताता चलू कि बिहार में 60 प्रतिशत जातीय-आर्थिक आरक्षण पहले से ही लागू है। 35 प्रतिशत मूल बिहारी महिलाओं के इस आरक्षण के बाद यह बढ़ कर 74 प्रतिशत पर पहुंच जाएगा, जिसका सीधा असर अनारक्षित वर्ग पर पड़ेगा जिसके लिए बस 14 प्रतिशत सीटें ही बचेंगी। वर्तमान में राज्य में 18 प्रतिशत अतिपिछड़ा, 12 प्रतिशत अनु पिछड़ा, 16 प्रतिशत एससी, एक प्रतिशत एसटी और ओबीसी महिलाओं का 3 प्रतिशत आरक्षण लागू है। इसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का 10 प्रतिशत भी है।

बहरहाल,पाठकों को बताता चलू कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई केबिनेट की बैठक में इसका फैसला (आरक्षण देने का) लिया गया है।

हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला आरक्षण को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने यह घोषणा की है कि बिहार राज्य की मूल निवासी महिलाओं को अब राज्य की सभी सरकारी सेवाओं, संवर्गों और सभी स्तरों के पदों पर सीधी नियुक्ति में 35 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा तथा यह आरक्षण सभी प्रकार की सरकारी नौकरियों पर लागू होगा। पाठकों को बताता चलू कि बिहार में 60 प्रतिशत जातीय-आर्थिक आरक्षण पहले से ही लागू है। 35 प्रतिशत मूल बिहारी महिलाओं के इस आरक्षण के बाद यह बढ़ कर 74 प्रतिशत पर पहुंच जाएगा, जिसका सीधा असर अनारक्षित वर्ग पर पड़ेगा जिसके लिए बस 14 प्रतिशत सीटें ही बचेंगी। वर्तमान में राज्य में 18 प्रति. अति पिछड़ा, 12 प्रतिशत अन्य पिछड़ा, 16 प्रति. एससी, एक प्रतिशत एसटी और ओबीसी महिलाओं का 3 प्रति. आरक्षण लागू है। इसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का 10 प्रति. भी है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि देश में सभी राज्य सरकारें महिलाओं को कुल पदों में अपने-अपने हिसाब से आरक्षण देती रही हैं। जैसे कि उत्तराखंड में सरकारी भर्तियों में महिलाओं के लिए 30 फीसदी आरक्षण, मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 35 फीसदी आरक्षण, यूपी में राज्य सरकार की ओर से 20 फीसदी आरक्षण, केरल-कर्नाटक, तेलंगाना-पंजाब में 33 फीसदी, और त्रिपुरा में 33 फीसदी पद नौकरियों में आरक्षित किए गए हैं। संशोधन संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत राजस्थान की भजनलाल सरकार ने कुछ समय पहले राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम-1989 में संशोधन करते हुए सीधी भर्ती में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने का फैसला लिया था। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भाजपा सरकार ने कुछ दिन पूरे होने पर महिलाओं को शिक्षक भर्ती में 50 फीसदी आरक्षण देने का ऐलान किया था। हालांकि , विधि विभाग ने इस प्रस्ताव पर आपत्तियां जताई और फाइनल लौटा दी।इसी प्रकार से महिला आरक्षण बिल के पास होने के बाद संसद और विधानसभाओं(विधायिका) की 33 फीसदी सीटों पर महिला आरक्षण की बात कही गई है, जो साल 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार के कार्यकाल में पास हुआ था। बहरहाल, कहना गुलत नहीं होगा कि बिहार में चार माह के भीतर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक प्रकार से महिलाओं पर लगाया गया बड़ा दांव हो कहा जा सकता है, ताकि आने वाले विधानसभा चुनावों में उनकी पार्टी जीत हासिल कर सके। गौरतलब है कि साल 2005 में महिला सशक्तिकरण की बात करके ही नीतीश कुमार सत्ता में आए थे। बहरहाल, राजनीतिक दल और उनके नेता यह बात अच्छी तरह से जानते हैं कि आज के समय में महिला वोटरों की चुनावों में बहुत बड़ी भूमिका होती है और महिला वोटर नायिका बनकर उभरती हैं। स्वयं नीतीश कुमार

भी इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि आज के समय में बड़ी संख्या में महिला मतदाता अपने मतधिकार का प्रयोग करने लगी हैं। आंकड़े बताते हैं कि बिहार में साल 2020 के विधानसभा चुनाव में तो पुरुषों के मुकाबले 5.24 फीसदी अधिक महिलाओं ने वोट डाले थे। जानकारी के अनुसार वर्ष 2020 के बिहार विधानसभा चुनावों में 59.69 फीसदी महिलाओं ने वोट दिए थे और 26 महिलाएं जीतकर आगे आई थीं। हालांकि, वर्ष 2015 में 28 महिलाएं जीतकर विधानसभा पहुंचीं थीं। नीतीश कुमार जानते हैं कि महिलाओं के वोट हासिल कर वे सत्ता की चाबी तक आसानी से पहुंच सकते हैं। पाठकों को बताता चलू कि चुनाव से पहले नीतीश कुमार, ने मतदाताओं को लुभाने के लिए लाभकारी योजनाओं की राशि भी बढ़ाई। उपलब्ध जानकारी के अनुसार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि बढ़ाकर 60 लाख परिवारों को फायदा पहुंचाया है। इतना ही नहीं,नीतीश कैबिनेट ने सीता मंदिर के लिए ?883 करोड़ की बड़ी राशि देने का ऐलान किया।इसी प्रकार से बिहार में बुजुर्गों और दिव्यांगजनों को मिलने वाली पेंशन राशि 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये प्रतिमाह कर दी गई,जिसे जुलाई से मिलने की बात कही गई है। और तो और नीतीश ने राज्य की युवा आबादी को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए बिहार युवा आयोग की भी घोषणा की है। पाठकों को बताता चलू कि युवा आयोग इस बात की निगरानी करेगा और सुनिश्चित करेगा कि राज्य के युवाओं को राज्य के भीतर निजी क्षेत्र के रोजगार में प्राथमिकता दी जाए। चुनावों से पहले उच्च जाति आयोग, अनुसूचित जाति (एससी) आयोग, महादलित आयोग और मछुआरा आयोग का गठन करने की बात कही भी मुख्यमंत्री ने कुछ समय पहले कही थी। कहना गुलत नहीं होगा कि नीतीश कुमार इस प्रकार की घोषणाओं से सामाजिक संतुलन और सियासी समीकरणों को साध रहे हैं। कुल मिलाकर, सच तो यह है कि बिहार चुनाव से पहले जनता दल (यूनाइटेड) ने

‘पच्चीस से तीस, फिर से नीतीश’ का नारा दे दिया है। बहरहाल, पाठकों को बताता चलू कि बिहार देश के उन शुरुआती राज्यों में एक है, जिसने पंचायत और स्थानीय निकायों में आधी आबादी के लिए पचास फीसदी सीटें आरक्षित की हैं और बिहार सरकार के इस कदम ने यहां की स्त्रियों में जबर्दस्त राजनीतिक जागरूकता पैदा की है। नीतीश कुमार ही नहीं, बिहार में अब हरेक राजनीतिक दल विशेषकर महिला वर्ग को व युवाओं को आकर्षित करने में जुट गया है। गौरतलब है कि काग्रिस महागठबंधन ने बिहार राज्य में इस वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव के पूर्व राज्य महिलाओं को सशक्त करने के लिये ‘माई बहिन मान योजना’ कैपेन लॉन्च किया है। इस योजना के तहत महिलाओं को प्रतिमाह 2,500 रुपये की सम्मान राशि सीधे उनके खाते में भेजी जाएगी। इधर, राजद नेता तेजस्वी यादव बेरोजगारी और डोमिसाइल के मुद्दे को जोर-शोर से उठा रहे हैं। ऐसे में, नीतीश सरकार के महिला आरक्षण के इस नीतिगत दांव व अन्य दावों के अच्छे तरह से समझा जा सकता है। वैसे भी महिला आरक्षण बिहार जैसे राज्य में एक बड़े सामाजिक बदलाव का वाहक बन सकता है। वैसे देखा जाए तो नीतीश कुमार का महिलाओं को 35 फीसदी आरक्षण का यह फैसला स्वागत योग्य ही कहा जा सकता है, क्योंकि इससे महिलाओं को आगे बढ़ने के सुअवसर प्राप्त होंगे और वे स्वावलंबी, सशक्त बन सकेंगी। समाज से लैंगिक खाई भी कम हो सकेंगी, क्यों कि बिहार जैसे राज्य में आधी भी बहुत कम महिलाएं ही सरकारी नौकरियों में हैं। चुनाव अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन यदि चुनावों के बहाने से ही समाज में कुछ अच्छा हो रहा है,तो इससे काबिले-तारीफ माना जा सकता क्या हो सकती है। किसी समाज में यदि कोई महिला आन आगे आती है तो इससे देश व समाज की तरक्की ही होती है। बहुत अच्छा हो यदि अन्य राज्य सरकारें भी महिलाओं के लिए ऐसे विशेष प्रबंध करने के लिए आगे आएँ।



आयोजन

अवधेश कुमार

लेखक दिल्ली निवासी वरिष्ठ पत्रकार हैं।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राजधानी दिल्ली में 4 से 6 जुलाई तक आयोजित तीन दिवसीय अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक वैसे तो राजनीतिक दलों एवं मीडिया के लिए किसी हलचल मचाने वाले समाचार का कारण नहीं बना, पर इसके महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता। संघ ने संगठन की दृष्टिसे पूरे देश को 11 क्षेत्र एवं 46 प्रांतों में बांटा है। बैठक में सरसंघचालक, सरकायवाह एवं सहसयर्कार्यवाह सहित केंद्रीय पर्याप्तिकारियों , सभी प्रांत प्रचारक, सह प्रांत प्रचारक, सभी क्षेत्र प्रचारक, सह क्षेत्र प्रचारक के साथ 32 संघ प्रेस प्रतिनिधि एवं प्रासप निर्माहित होते हैं। निरोधियों के क्षेत्र तैयारी के विपरीत बैठक हमेशा शांत संतुलित व्यवस्थित माहौल में संपन्न होता है। इसमें सामान्य दलीय राजनीति पर विचार के लिए गुंजाइश नहीं होती है। जितनी जानकारी हो इसका महत्व समझ में अपने -आप आ जाता है। यानी संघ और इससे जुड़े संगठनों का संपूर्ण पत्र प्रतिनिधि नेतृत्व की वहां उपस्थिति केवल मिलने जुलने के लिए तो नहीं हो सकती। संघ का गहराई से अध्ययन करने वाले या निक्ट से उसकी गतिविधियों पर निष्पक्ष दृष्टि रखने वाले जानते हैं कि बैठकों के सभी सत्रों के विषय एवं प्रासप निर्माहित होते हैं। निरोधियों के क्षेत्र तैयारी के विपरीत बैठक हमेशा शांत संतुलित व्यवस्थित माहौल में संपन्न होता है। इसमें सामान्य दलीय राजनीति पर विचार के लिए गुंजाइश नहीं होती है। जितनी जानकारी हो भाजपा अध्यक्ष के चुनाव को लेकर बाहर की उकंटन के विपरीत यह चर्चा में भी नहीं आया। संघ के वर्ष में कुछनिश्चित आयोजन हैं जिनमें प्रांत प्रचारक बैठक भी शामिल है। मार्च में अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक तथा अप्रैल से जून तक प्रशिक्षण वर्गों के संपन्न होने के बाद यह बैठक आयोजित होती है। इसलिए इसमें देश भर के पूरे वृतांत तथा भविष्य के संगठन की योजनाओं पर फोकस रहता है।

वैसे भी संघ का मुख्य फोकस संगठन, समाज जागरण तथा समाज परिवर्तन है तो इसका फोकस बनी रहेगा। जैसा हम जानते हैं इस वर्ष विजयादशमी वाली 2 अक्टूबर से संघ शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर रहा है। पिछले काफी समय से आगामी 2 अक्टूबर से लेकर 2 अक्टूबर 2026 तक इसके आयोजनों और कार्यक्रमों

शताब्दी वर्ष में समाज परिवर्तन के लिए सक्रिय संघ

को लेकर गंभीर चर्चा हमारे सामने आते रहे हैं। स्वाभाविक ही इस समय की अधिकतर बैठकों का केन्द्र बिंदु शताब्दी वर्ष ही होगा। जितनी जानकारी है संघ अन्य संगठनों या राजनीतिक दलों की तरह शताब्दी वर्ष पर कोई एक बड़ा आयोजन करने की जगह इसका उपयोग संगठन विसुत्तर, हिंदुत्व केंद्रित विचार को अधिकतम लोगों तक पहुंचाने तथा समाज परिवर्तन की दृष्टि से कार्यक्रमों के आयोजनों के लिए कर रहा है। योजना अनुसार नागपुर में 2 अक्टूबर को वार्षिक विजयादशमी उत्सव में सरसंघचालक डॉ मोहन भागवत की हर वर्ष की तरह उपस्थिति एवं संबोधन के साथ उसी दिन देशभर में शाखा/ मंडल/ बस्ती के स्तर पर उत्सव आयोजित होंगे। विशेष अभियानों के तहत स्वयंसेवक घर-घर जाकर संपर्क करेंगे। गृह संपर्क अभियान के दौरान स्वयंसेवक संघ साहित्य देकर बातचीत करेंगे। सरसंघचालक मोहन भागवत का विशेष संवाद कार्यक्रम चार शहरों दिल्ली, मुंबई, कोलकता, बैंगलुरु में आयोजित होगा , जिसमें आमंत्रित लोगों के समक्ष अपनी बात रखेंगे तथा संवाद भी होगा। संघ ने शताब्दी वर्ष में समाज परिवर्तन की दृष्टि से पांच परिवर्तन का विचार रखा है जिसमें सामाजिक समरसता,परिवार यानी कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण, स्व का बोध और नागरिक कर्तव्य शामिल है। दरअसल , मोहन भागवत ने 2021 में समाज परिवर्तन की दृष्टि से ये पांच विषय सामने रखे थे और संघ इस पर काम कर रहा है। इससे संबंधित अलग-अलग सामाजिक सद्भाव समेलन आयोजों का परिवारों का तथा इसी दृष्टि से संवाद आदि के सतत कार्यक्रम हैं। स्वाभाविक ही प्रांत प्रचारक बैठक में कहा-कहा कितने और को से कार्यक्रम हो सकते हैं तथा उनमें अपेक्षित संख्या की कितनी संभावना होगी, व्यवस्था कैसे हो रही है आदि विषय विद्वत्तार चर्चा में आए। बैठक से निकलकर सभी प्रांत और क्षेत्र प्रचारक कार्यक्रमों की पूर्व तैयारी की दृष्टि से बैठकें, एकत्रीकरण आरंभ कर देंगे। इनकी गहराई से समीक्षा करें तो साफ हो जाएगा कि समाज और सत्ता में व्याप्त विद्वरुप्ताओं की निंदा , आलोचना, विरोध से परे समाज की सहभागिता से सकारात्मक परिवर्तन का उद्देश्य ही इसके पीछे है। जाति भेद से परे हटकर सामाजिक समरसता के अंतर्गत समाज में सद्भाव बढ़े,

परिवारों की पर्यावरण अनुकूल जीवनशैली बने, हममें स्व-बोध यानी अपने राष्ट्र की महान विरासत, महान सभ्यता -संस्कृति -धर्म -अध्यात्म, फोटो में व्याप्त समाज संगठन उपलब्धियां आदि के प्रति गौरव व्याप्त हो, कुटुंब यानी परिवार के सभी सदस्यों- संबंधियों में आत्मीयता व संस्कारों की वृद्धि हो तथा लोग नागरिक के नाते अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो जाएं तो धीरे-धीरे संपूर्ण समाज और देश की स्थिति कितनी सकारात्मक, सहकारी और सशक्त होगी इसकी कल्पना आसानी से की जा सकती है। पहले से इन विषयों पर चर्चाएं हो रही हैं, उनके साहित्य आदि प्रकाशित हैं, बैठकों में भी इन पर मंथन हो रहा है और प्रांत प्रचारक बैठक में संगठन के स्तर पर इसे आगे बढ़ाने की योजना तय हो गई है इसलिए कार्यक्रम भी संपन्न होंगे। विश्व में ऐसा कोई संगठन नहीं होगा जो इतना तय करें सब कुछ उसी के अनुरूप हो जाए और कि त्वरित लक्ष्यों की प्राप्ति भी। इसलिए यह नहीं कह सकते कि सब कुछ कल्पना के अनुरूप भी हो जाएगा और सोरे लक्ष्य भी प्राप्त हो जाएंगे किंतु उस दिशा में कुछ हद तक सफलता मिलेगी यह निश्चित है। जितनी संख्या में व्यक्तियों के अंदर पांच परिवर्तन के लिए भाव जाग्री वह अपने स्तर पर कुछ ना कुछ करेंगे और समाज के स्तर पर जगह-जगह इन सबके सुखद परिणाम आते रहेंगे। वास्तव में संघ शताब्दी वर्ष की योजना ऐसा नहीं है जिन पर एक वर्ष तक काम किया और फिर। यह सतत आगे बढ़ते रहने के कार्यक्रम हैं। फिर जिनमें से सब जगह के दौरान संघकर्मी होगा उनके आगे शांखों प्रशिक्षकों आदि की दृष्टि से भी उपयोग की योजनाएं हैं। यानी जो जुड़े वह छूट नहीं इसकी कोशिश भी होगी। त्वरित परिवर्तन तात्कालिक आंदोलनों से होती है किंतु स्थायी सतत परिवर्तन और प्राप्ति्यों के लिए अनवरत ऐसे ही समाज के अंदर स्वतः अभियांत्र संचालित होते रहना आवश्यक होता है। संघ की यही कार्य शैली दिखती है।

चूँकि स्थापना के कुछ समय बाद से ही संघ के नियमित हर वर्ष प्रशिक्षण वर्ग आयोजित होते हैं, इसलिए उसे स्वयंसेवक और कार्यकर्ता के रूप में युवा वर्ग उपलब्ध होते हैं। इसी वर्ष आयोजित कुल 100 प्रशिक्षण वर्गों में से 40 वर्ष से कम आयु वर्ग के स्वयंसेवकों के लिए आयोजित 75 में 17, 609

स्वयंसेवकों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया जबकि प्रकार 40 से 60 वर्ष की आयु के 25 वर्गों में 4270 शिक्षार्थियों ने भाग लिया। इन वर्गों में देश के 8812 स्थानों से स्वयंसेवकों की सहभागिता रही। आया चाहे संघ की कितनी कटु आलोचना करिए किंतु सीएफ़, क्या भारत या दुनिया में कोई दूसरा संगठन इस स्तर पर नियमित प्रशिक्षण वर्ग चलाता है? स्वयंसेवकों में केवल शाखा के कार्यक्रम तक का ही प्रशिक्षण नहीं होता उसकी रचि के अनुसार सेवा या अन्य क्षेत्रों में जो कार्य समाज की दृष्टि से वे कर सकते हैं उनसे जुड़े कुछ निश्चित क्षेत्रों में कार्य करने में सक्षम बनाने योग्य या उन्नयन का प्रशिक्षण मिलता है। बैठक है तो इस बीच देश और दुनिया की घटनाएं भी चर्चा में अवश्य आएंगी। अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेडकर ने पत्रकारों के प्रश्न के उत्तर में कहा कि भारत की सभी भाषाएं राष्ट्र भाषाएं हैं, और संघ का मानना है कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए। भाषा संबंधी संघ की सोच अनेक बार सार्वजनिक रूप से रखी जा चुकी है फिर भी विरोधी यही कहते हैं कि संघ केवल हिंदी की ही बात करता है। एक बार पुनः स्पष्ट करने के बाद शायद दुष्प्रचार करने वाले बाज आएं।

पहलामान हमले से लेकर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान के स्थानीय अनुभवों तथा लोगों की प्रतिक्रियाओं की इससे ज्यादा अधिकृत जानकारी किसी संगठन को नहीं प्राप्त हो सकती। इस पीछेक से भविष्य में ऐसी चुनौतियों से निपटने को लेकर समाज व संगठन के साथ सरकार के लिए भी कुछ दिशा मिलेगी। प्रप्रगाराज में आयोजित महकुंभ में संस्कृतिक पुनर्जागरण का विराट स्वस्व प्रदर्शित हुआ। उससे बने वातावरण को समतान आध्यात्मिक मूल्यों के साथ हिंदू समाज की एकता के सुदृढ़ीकरण की दृष्टि से क्या हो रहा है क्या कर सकते हैंनिश्चय ही ये महत्वपूर्ण विषय हैं हर बैक में इसकी चर्चा हो रही है। डिजिटल माध्यम के नकारात्मक उपयोग से समाज के अंदर बढ़ रही समस्याओं का समाधान कैसे हो इस पर भी चर्चा होने की सूचना है। जैसा ऊपर बताया गया पूरी बैठक संगठन और कार्यक्रमों पर केंद्रित रही, संघ और विविध संगठनों के संगठन से संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे, इसलिए इसका प्रतिलफल धरतल पर दिखाई देगा।

पुलों की शामत और सरकारी मशीनरी



कटाक्ष

प्रीतम लखवाल

लेखक व्यंग्यकार हैं।

यह सर्वथा सत्य है, जो उठा है, खड़ा है या चलायमान है। वह निश्चित ही गिरगा। इसमें कोई तर्क इसलिए काम नहीं करेगा क्योंकि यह सब क्रियाएं प्रकृति के अधीन है। प्रकृति इन दिनों मनुष्यों के अधीन है। मनुष्य सरकार के अधीन है और सरकार इन्हीं मनुष्यों की निष्ठा भक्ति के अधीन है। पृथ्वी भू-गोल का हिस्सा है। भूगोल हमने पढ़ा है। इसमें नदियां भी हैं, पहाड़ भी हैं तो झरने, खाइयां और खूप भी हैं। झरने की प्रकृति है कि वह गिरता है। खाइयां गिराने का भाव पैदा करती हैं। पहाड़ खुद भी गिरने और दरकने को आतुर रहते हैं, लेकिन जो निर्मित हैं, वह कैसे गिर सकता है?

गिरने के भाव का उसमें अभाव है, क्योंकि कमीशन के रसायन से उसे मजबूत जोड़ जो मिलता है। भारत में ही पुल गिरते हैं। ऐसा नहीं है। पुल तो बनते-बनते गिर जाते हैं तो बने बनाए भी गिर जाते हैं। सारे इंजीनियर ये माथा खापा रहे हैं कि आखिर ये पुल भारी भरकम कमीशन के सॉल्यूशन से बनाए थे, फिर कैसे गिर रहे हैं। वे इस बात पर भी हेरान हैं कि आखिर टेक्नोलॉजी में कहाँ सूत भर की भी कमी रह रही है। वे ठेकेदार पर आंखें तोरे रहे हैं। ठेकेदार बोलाता है-माई-बाप आपने जो डिजाइन, जो रेश्यो दिया, उसी से उस पुल का निर्माण किया, जो आत्महत्ता बन गया। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था।

इतने में एक बयोवृद्ध इंजीनियर, जिसे सेवानिवृत्ति का तमगा और आधी हाल ही में थमाया गया था। वहां आ गया, जहां पुल के गिरने पर मातम कम अपनी इंजीनियरिंग पर अधिक रौन-धौना चल रहा था।

उसके आने के बाद एक सुसन्नाप्त सा दिखने वाला इंजीनियर बोला-महोदय, आप ही बताइए कि आखिर, 100 साल की उम्र साधकर बनाए गए पुल 50 भी पार नहीं कर पा रहे। कुछ बनने से ही पहले गिरने को लालायित रहते हैं। वृद्ध इंजीनियर बोला- इसमें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके लिए पृथ्वी ही दोषी है। अब सबके मुंह खुले रह गए और उसमें ईमानान की हवा प्रवेश कर आत्मा को ठंडक पहुंचाने लगी। वृद्ध इंजीनियर फिर बोला-फिर भी कुछ एक्सपयूज्ड हैं तो अपन सब भू-गर्भ शास्त्री के पास चलते हैं। वे सब एकत्र होकर भू-गर्भ शास्त्री के पास पहुंचे। वे अपनी प्रयोगशाला में कुछ न्यू नार्मल करने के चक्कर में बा-बा अपने बाल तोगे जा रहे थे। सभी ने उनको यथा योग्य किया। उन्होंने पलटे बिना ही उन्हें हाथ के पता से बैठ जाने को कहा। सभी बैठ गए। भू-गर्भशास्त्री पलटे और उनसे मुखातिब होकर बोले-कैसे आना हुआ। सभी ने कारण बताया। पुल धराशायी हो रहे हैं। हम कोई कसर नहीं छोड़ते। हूं...

अब भू-गर्भशास्त्री बोले- मैं वही प्रयोग कर रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। उन्होंने अपने हाथ में एक बाल लेकर आकाश की ओर उछाली और वह चंद सेकंड में ही नीचे गिर गई। वे बोले-समझो? सबने नहीं में गर्दन हिला दी। वे फिर बोले-पेदा है आपने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का नियम तो पढ़ा ही होगा, लेकिन पृथ्वी के गिरत्वाकर्षण आपको किसी ने नहीं पढ़ाया।

यह सब पृथ्वी के गिरत्वाकर्षण के कारण ही हो रहा है। जो जितना गिरना चाह रहा है, गिर रहा है। इसमें पुल, मानवता, इंसान, नेता, अधिकारी और मशिनरी सब शामिल है। सभी ने समाधान पूछा- भू-गर्भ शास्त्री बोले- जब तक गिरत्वाकर्षण के प्रभाव से मुक्त नहीं होंगे। यह सब होते रहेंगे। सभी अपना सा मुंह लेकर वहां से खाना हो गए और भू-गर्भ शास्त्री मुस्कान बिखेर कर पुनः लैब में घुस गए।

दिल जो दीवाना था, बाग-बाग हुआ..?

आशा (कोई लड़की का नाम नहीं) के विपरीत, मन के उल्टा घट जाता है तो मन दावानल सा सुलग उठता है,बंजर भूमि सा दिखने लगता है,अगला परत, सुस्त,लस्त,होकर लगाने लगता है गस्त।

ज्ञानी लोग बक गए हैं कि मन एक पंछी है इसे पिंजरे में मत कोंडो, घेरों,वो रुकेगा नहीं,उसे जितना उड़ाना है उड़ालो। आजकल का सॉलिड दिल तो इतना मजबूत है कि पिंजरा तोड़कर फुर्र हो जाता है और लोगों को पता भी नहीं चलता है। आजकल की बेंडी पीढ़ी तो दिल का कहना भी नहीं डालती है,अपने मर्जी माफिक बेजुलुल हकतें करती रहती हैं। तुमने उसे नियंत्रित करने, दबाने का दुःसाहस किया तो तुम खुद खुद सुझिद्ध हो जाओगे।इंसान की प्रसन्नता उसके मनमाफिक कार्य होने पर होती है तभी वो सेंट-परसेंट खुश होता है।शायर कहेते है दिल का यकीन नहीं करना चाहिए ये गिरगिट सा रंग बदलता है।ये किसी पर भी आ सकता है, टूट सकता है, गले पड़ सकता है।ये अनियंत्रित वस्तु है। इसे नियंत्रित करने में सारी उम्र लगा जाती है,खप जाती है।

ज्यादा नियंत्रित करने वाले साधु सत बन जाते हैं और जो दिल के कहने में उसके गुलाम बन कर चलते हैं बड़े शैतान,रंगीले,शातिर बन जाते है।दिल पर दिलदार गीतकारों ने कई गाने बड़े दिल से लिखे हैं। नवगुलाम प्यार में दिल पर तीर चलाते हैं।एकधरा तीर कलेजो में लगात है और प्यार का पौधा फनफने लगता है। इस दिल

की तीर से खासी पटती है,दोनों मे गहरी यारी है।जभी तो तीर कलेजे पर लगता है और आदमी सुधर जाता हैं।कई बार बात दिल पर लग जाती है और आदमी गठन बांध लेता है।मर्यादा तोड़ देता है।कई दफा तो कोई बात दिल के अगर-पार हो जाती है, जिसे भुला पाना मुश्किल होता है? उसमें आमूल चूल परिवर्तन आ जाता है। जिसके कलेजे पे पुरो नही लगता,कई बात नहीं लगती,चुभती उसे लोग ‘मिसडूला’ कहते है, मोटी चमड़ी का बेदई दिल में कलेजा रहता है या कलेजे में दिल फंसा रहता है। दोनों आपस में आमने सामने रहते हैं। इसका सीधा संबंध दिमाग से रहता है।

दिल से भेजा नहीं,भेजे से दिल संचालित होता है। जो दिलफेंक लोग रहते हैं उन्हें दिलवाले और जो दिल की नहीं सुनते हैं वो दिलजलते रहते हैं? बहुत से दिल के गुलाम होते है,कोई-कोई दिल का बादशाह रहता है। बिरले होते है जो दिल को अपने कंट्रोल में रखते हैं? युवा पीढ़ी दिल के नियंत्रण में, प्रौढ़ लोग दिल से दुःबुजुर्ग दिल से परे और साधु संत दिल से खरे रहते हैं। मनुष्य के शरीर में दिल की बड़क कदर है।वो धड़कता है तो सब कुछ है,सुन्न होता है तो सूनी सड़क है,बंद हो गया तो खत्म सब तड़क-भड़क है। याद रह जाता है लड़क(पन) है। चिकित्सा विज्ञान में भी इसकी धक-धक की कीमत है, इसके भक-भक होते ही व्यक्ति को एम्बुलेंस में चढ़ा दिया जाता है और परिजनों को बिल थमा दिया

जाता है। भुगतान नहीं करने पर इस माटी को परिजनों को नही लौटाया जाता है ताउम्र मनुष्य करता है चक-चक,मेहनत कर जाता है थक-थक, फिर कोसता रहता है अपना ‘लक-लक’जीते जी वो करता रहता है एक-दूजे पर शक-शक,खुद की ढींग हंकने पर आदमी करता रहता है फक-फक,हमारे उधर गोंडवाना में भूख मरता आदमी हमेशा करता रहता है छक-छक?

यहां उक्त से तात्पर्य और चाहिए और पोंसिये। ‘ मत कमाऊ मीठा भोजन’ किस्य के लोग जीवन में उपलब्धियों के नाम पर होते हैं एक (बदरङ्ग) सार यह है कि जिलकाल की गाड़ी दिल से ही दौड़ती है। दिल मजबूत हो तो सब ठीक है वरना काय का ठीक भय्या? दिल एक ऐसी जगह है जहां, सारे दर्द और खुशियां रहती हैं।यह एक ऐसा स्थान है जहां,प्रेम और दर्द का संगम होता है। दिल तो बस एक मांस का लोथ है,लेकिन इसमें सारी दुनिया समाई है। यह एक ऐसी चीज है जो, हर किसी के पास होती है लेकिन किसी की भी नहीं है। दिल पर व्यंग्य करना आसान है, लेकिन इसे समझना मुश्किल है। यह एक ऐसी चीज है जो, हर किसी को अपने वश में कर लेती है।दिल की कीमत क्या है, यह कोई नहीं जानता। लेकिन यह एक ऐसी चीज है,जिसके बिना जीवन सूना है। दिल से अधिक सुरक्षित स्थान नही है संसार में मरार सबसे ज्यादा लोग गावब भी यही से होते है?



हर वर्ष 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस आते ही हम अचानक आँकड़ों और योजनाओं की तरफ देखने लगते हैं। सरकारें जनसंख्या नियंत्रण की दिशा में किए गए प्रयासों का लेखा-जोखा प्रस्तुत करती हैं और समाज के प्रबुद्ध वर्ग में आबादी को लेकर चर्चाएँ होने लगती हैं। लेकिन यह दिन केवल जनसंख्या वृद्धि को संकट कहने भर का नहीं है – यह दिन सोचने की क्षमता, नीति-निर्माण के दृष्टिकोण, और सामाजिक समावेशन के स्तर का भी मूल्यांकन करने का अवसर है।

भारत आज विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है। 2024 तक भारत की जनसंख्या 1.43 अरब का आंकड़ा पार कर चुकी है। यह संख्या अकेली नहीं है, यह हमारे सामाजिक और संसाधनात्मक ढाँचे पर एक गंभीर दबाव बन चुकी है। चीन को पीछे छोड़ते हुए भारत ने यह स्थिति पाई है, लेकिन क्या यह उपलब्धि है या चुनौती – इसका उत्तर सबको अपने आसपास के जीवन से मिल सकता है। क्या हम इस बढ़ती जनसंख्या को संभालने के लिए मानसिक, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय दृष्टि से तैयार हैं? क्या हमारी सोच, हमारी योजनाएँ और हमारी व्यवस्थाएँ उतनी ही विकसित हुई हैं, जितनी तेजी से जनसंख्या बढ़ी है?

जनसंख्या को अक्सर एक अवसर की तरह देखा जाता है – कहा जाता है कि भारत की 66 प्रतिशत जनसंख्या कार्यशील आयु वर्ग में है। यह डेमोग्राफिक डिविडेंड देश के लिए पूंजी का काम कर सकती है। लेकिन यह लाभ तभी मिलेगा जब यह जनसंख्या शिक्षित, स्वस्थ और कुशल हो। यदि संसाधनों और व्यवस्थाओं में समरसता नहीं होगी, तो

प्लास्टिक से विनाश, कागज से समाधान



प्लास्टिक प्रदूषण के विरुद्ध वैश्विक चेतना के प्रतीक और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में प्रतिवर्ष 12 जुलाई को ‘विश्व पेपर बैग दिवस’ मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को प्लास्टिक के बजाय पर्यावरण-अनुकूल विकल्पों की ओर प्रेरित करना है ताकि पृथ्वी को प्लास्टिक के कहर से बचाया जा सके। दरअसल प्लास्टिक की थैलियाँ आज जिस भयावह रूप में हमारे पर्यावरण, पारिस्थितिकी तंत्र और स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचा रही हैं, उस पर नियंत्रण के लिए पेपर बैग एक मजबूत समाधान बनकर उभरा है। दुनिया में हर साल 500 अरब से भी अधिक प्लास्टिक बैग का उपयोग किया जाता है, जो न केवल हमारी सड़कों, नदियों और समुद्रों को भर देता है बल्कि जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता संकट और मानव स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों को भी जन्म देता है। प्लास्टिक बैग इतने खतरनाक होते हैं कि समुद्री जीव-जंतु इन्हें भोजन समझकर निगल लेते हैं, जिससे उनकी मौत हो जाती है। समुद्री पक्षियों की 100 से अधिक प्रजातियाँ प्लास्टिक खा रही हैं, वहीं 250 से अधिक प्रजातियों को प्लास्टिक में उलझे हुए देखा गया है। समुद्री शेरों और सील की कई प्रजातियाँ में आठ प्रतिशत तक की उलझाव दर देखी गई है। यह स्पष्ट संकेत है कि प्लास्टिक बैग केवल कचरा नहीं बल्कि धरती पर एक घातक आपदा बन चुके हैं।

प्लास्टिक की थैलियाँ पारदर्शी, सस्ती, हल्की और सुविधाजनक होती हैं लेकिन इनका पर्यावरणीय मूल्य अत्यंत महंगा है। ये नालियों को जाम करती हैं, जिससे शहरी बाढ़ की समस्या बढ़ती है। खेतों में प्लास्टिक थैलियों की मौजूदगी मिट्टी की उर्वरता को प्रभावित

पानीपुरी - एक अधूरी कहानी



स दिन, याने कि 12 जुलाई को विश्व पानी पूरी दिवस था। ईमान से कहूँ तो मुझे इसका जरा भी इल्म नहीं था। अन्यथा सभी चटोरी, पेटुओं, भुखखड्डों और खवैयों को इस विलक्षण दिवस पर हार्दिक बधाई देने में इतना विलंब क्यों करता ? वो तो हुआ यों कि पिछली बस्ती में रहने वाले जगमोहन का बेटा छिछू दो दिन मेरी गाड़ी साफ करने नहीं आया। तीसरे दिन उसने बताया कि शहर के एक तीन सितारा होटल के इंडियन कुजिन के मेन्यू में उस खास दिन पर पानीपुरी शामिल की गई थी। रोज़ ग्लॉस कॉलेज के सामने खोमचा लगाने वाले उसके पिताजी ने झकीस फ्लेवर वाली पानीपुरी का वहां स्टाल लगाने का मौका हथिया लिया था। छिछू का असली नाम तो अंशुल था। उसकी मां उसे अंशुल कहके बुलाती थीं। लेकिन पानीपुरी की पूरियों में आलू भरने के लिए अंगूली से छेद करके अपने पिता को देने का काम वो इस तेजी, लयकारी और नफासत से किया करता था कि बस्ती के लोग उसे छिछू के नाम से बुलाने लगे थे। उसी ने बताया कि वो दिन खास इसलिए था कि गमूल बाबा ने उसे विश्व पानीपुरी दिवस घोषित कर दिया था।

यह जानकर मेरा भी सीना 56 इंच का हो उठा कि हमारी पानीपुरी अब लोकल से ग्लोबल हो गई है। ये कोई साधारण बात नहीं है। ये उन सभी स्वादाभिलाषियों याने कि चटोरीयों की ज़िद, जीवट और जिजीविषा का परिणाम है, जिन्होंने अपने हाजमे और हाजत की परवाह किए बगैरे पानीपुरी के प्रति अपना जुनून को हमेशा ज़िंदा रखा और उसे इस मुकाम तक पहुंचाया। इसीलिए उन सभी पानीपुरी प्रेमियों को शुभकामनाएं जो नितर बिना गिने पानीपूरी को पूरी उदरता से उपस्थ करके रहते हैं। हींग के पानी से उष्का लगे तो इसली के पानी से उसके दो दांत खट्टे करते रहते हैं। पर किसी भी हालत में मैदान नहीं छोड़ते। खट्टे दांतों की सिहरन को पुदीने के पानी से दूर करना आयुर्वेद सम्मत है या नहीं इस बहस में वे नहीं उलझते। इससे पहले कि खट्टे दांत

यही विशाल जनसमूह असमानता, बेरोजगारी और असंतोष का कारण बन जाएगा। यह भी तथ्य है कि देश के 23 प्रतिशत युवा आज भी बेरोजगारी, अशिक्षा या प्रशिक्षण से बाहर हैं। लगभग 14.9 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जाते। यह केवल आँकड़े नहीं हैं, ये भविष्य के दरवाजों पर दस्तक देने वाली वास्तविकताएँ हैं। जिन्हें दर किनार नहीं किया जा सकता है।

बढ़ती जनसंख्या का सबसे प्रत्यक्ष प्रभाव हमारे पर्यावरण पर पड़ा है। शहरीकरण और औद्योगीकरण की अंधी दौड़ में पिछले पंद्रह वर्षों में देश के 13 लाख हेक्टेयर से अधिक वनक्षेत्र औद्योगिक परियोजनाओं को सौंपे जा चुके हैं। यह प्रक्रिया केवल जंगलों की कटाई नहीं, बल्कि जीवनशैली और पारिस्थितिकी दोनों की तबाही है। भारत के 14 शहर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन की रिपोर्ट में दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में गिने गए हैं। दिल्ली, पटना, कानपुर, गाजियाबाद, भिवंडी – ये केवल नाम नहीं हैं, वायुप्रदूषण के प्रतीक बन चुके हैं। नदियाँ मृतप्राय हैं, तालाब पाटे जा रहे हैं और भूजल स्तर तेजी से गिरता जा रहा है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत के 21 प्रमुख शहरों में 2030 तक भूजल समाप्त हो सकता है। यह संकट केवल पर्यावरण का नहीं, हमारे अस्तित्व का भी है।

जनसंख्या वृद्धि से जीवन स्तर पर भी गंभीर असर पड़ा है। ‘रेटी, कपड़ा और मकान’ हर भारतीय का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन क्या ये मूलभूत सुविधाएँ सभी को उपलब्ध हैं? 13.5 करोड़ लोग आज भी पक्के मकान से वंचित हैं। लगभग 19 करोड़ भारतीय कुपोषण के शिकार हैं। झुगियों में रहने वालों की संख्या 70 लाख से अधिक हो चुकी है, जिनके पास स्वच्छ जल, शौचालय और स्वास्थ्य सेवाएँ नहीं हैं। भारत में आज भी करीब 1.8 करोड़ लोग

विश्व पेपर बैग दिवस पर विशेष

इस गंभीर समस्या का एक सशक्त समाधान है ‘पेपर बैग’। पेपर बैग शत-प्रतिशत बायोडिग्रेडेबल होते हैं और कुछ ही हफ्तों में स्वयं तो समुद्री जीवों के लिए खतरा हैं, न ही भूजल या वायु प्रदूषण के कारक। पेपर बैग न केवल पर्यावरण-अनुकूल हैं बल्कि आज एक बड़ा आर्थिक अवसर भी बनते जा रहे हैं। भारत सहित कई देशों में पेपर बैग निर्माण का एक बड़ा उद्योग खड़ा हो रहा है, जो न केवल हरित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रहा है बल्कि रोजगार भी पैदा

करती है और जल के रिसाव को रोकती है, जिससे भूजल पुनर्भरण की दर में कमी आती है। प्लास्टिक कई शताब्दियों तक नष्ट नहीं होता और इसके जलाने से जो रसायन निकलते हैं, वे हवा और वातावरण को जहरीला बना देते हैं। यही कारण है कि अब इस पर गंभीर चिंता जताई जा रही है और दुनिया के कई हिस्सों में इसे प्रतिबंधित किया जा चुका है। भारत में भी इस दिशा में प्रयास किए जा चुके हैं। कई राज्य सरकारों ने प्लास्टिक पर आंशिक या पूर्ण प्रतिबंध लगाए हैं। साथ ही, राष्ट्रीय स्तर पर ‘स्वच्छ भारत अभियान’ और ‘सिंमल यूज प्लास्टिक प्रतिबंध’ जैसे कदमों से इस समस्या के समाधान की कोशिशें हो रही हैं। भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार, देश में प्रतिदिन लगभग 26 हजार टन प्लास्टिक कचरा पैदा होता है, जिसमें से 10 हजार टन का कोई निस्तारण नहीं होता। यही वह कचरा है, जो अंततः हमारे जलस्रोतों और समुद्रों तक पहुंचकर पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंचाता है।

इस गंभीर समस्या का एक सशक्त समाधान है ‘पेपर बैग’। पेपर बैग शत-प्रतिशत बायोडिग्रेडेबल होते हैं और कुछ ही हफ्तों में स्वयं विघटित होकर मिट्टी में मिल जाते हैं। वे न तो समुद्री जीवों के लिए खतरा हैं, न ही भूजल या वायु प्रदूषण के कारक। पेपर बैग न केवल पर्यावरण-अनुकूल हैं बल्कि आज एक बड़ा आर्थिक अवसर भी बनते जा रहे हैं। भारत सहित कई देशों में पेपर बैग निर्माण का एक बड़ा उद्योग खड़ा हो रहा है, जो न केवल हरित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रहा है बल्कि रोजगार भी पैदा



मेरी गुज़ारिश है कि पानीपुरी को ऐसाझूबैसा न समझा जाए। ये बड़ी महिमावान है। ये सवेत्र और सर्वसुलभ है। सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी। ये समाजवादियों के भी ज़्यादा पक्की समाजवादी है। ये बहुरूपी, बहुआयामी और बहुनामधारी है। कदाई में फूल गई तो फुल्की है। नहीं फूली, तो पापड़ी है। इसके बावजूद इसका मूलभूत तत्व अशुष्ण और सर्वत्र समान है। ये जहां भी गई, अपना स्वत्व साथ लेकर गई। कहीं ये पताशा है, कहीं फुचके। कहीं पुचका तो कहीं फुल्की। कहीं गोलगप्पा तो कहीं गुपचुप। वैसे गुपचुप नाम पर मेरी विनम्र असहमति है। इसकी तासीर से ये नाम मेल नहीं खाता। इसे खाने के साथथी, खाने के बाद भी, कुछ भी गुपचुप नहीं रह सकता। ये स्वाभावतः सामाजिक और सार्वजनिक व्यंजन है। फुल्की एक ऐसा व्यंजन है जो स्वर को भी उत्प्रेरित करता है। ये मानव के नश्वर शरीर में यातायात की समस्या के निदान के लिए ‘माणवीरोध’ दूर करता है। इसके सेवन से पदार्थ की तीनों अवस्थाएँ मानव शरीर में गति और ऊर्जा को प्राप्त करती हैं जिसकी उसे आमय से निर्गम तक यथासमय और

खुले में शौच के लिए मजबूर हैं। यह स्थिति केवल बुनियादी सुविधाओं की कमी नहीं दर्शाती, बल्कि यह हमारी सामाजिक प्राथमिकताओं और विकास की दिशा पर प्रश्नचिह्न लगाती है। हर वर्ष लाखों लोग गांवों से शहरों की ओर पलायन करते हैं। लगभग 90 लाख लोग प्रतिवर्ष शहरों की ओर आते हैं, रोजगार, शिक्षा और बेहतर जीवन की उम्मीद में। परंतु शहरों की स्थिति भी दयनीय है। वे पहले से ही भीड़ से भिरे हैं, बुनियादी सेवाएं चरमराई हुई हैं और नई आबादी को समाहित करने के लिए न योजनाएं हैं, न संसाधन। पलायन करने वाले लोग अधिकतर दिहाड़ी मजदूर, निर्माण कार्य में लगे श्रमिक, घरेलू सहायक या रिक्शा चालक बनते हैं। उनके बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, महिलाएं असुरक्षित परिस्थितियों में काम करती हैं और उनका जीवन अस्थायित्व के दायरे में सिमट जाता है। यदि इस समग्र परिप्रेक्ष्य में हम भारत के आदिवासी इलाकों की बात करें, तो तस्वीर और भी मर्मस्पर्शी हो जाती है। भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 8.6 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है। ये समुदाय प्राचीन, सांस्कृतिक और प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े रहे हैं, लेकिन आधुनिक विकास की दौड़ में सबसे अधिक हानिए पर इन्हें ही रखा गया है। मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पूर्वोत्तर राज्यों में स्थित आदिवासी क्षेत्र आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य और संचार जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। आदिवासी बच्चों में कुपोषण, शिशु मृत्यु दर और अशिक्षा की दर सामान्य से बहुत अधिक है।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट बताती है कि आदिवासी महिलाओं को गर्भावस्था और प्रसव के समय आवश्यक चिकित्सकीय सहायता नहीं मिल पाती। कई इलाकों में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचने के लिए दस से पंद्रह किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। बच्चों

विश्व पेपर बैग दिवस पर विशेष

इस गंभीर समस्या का एक सशक्त समाधान है ‘पेपर बैग’। पेपर बैग शत-प्रतिशत बायोडिग्रेडेबल होते हैं और कुछ ही हफ्तों में स्वयं तो समुद्री जीवों के लिए खतरा हैं, न ही भूजल या वायु प्रदूषण के कारक। पेपर बैग न केवल पर्यावरण-अनुकूल हैं बल्कि आज एक बड़ा आर्थिक अवसर भी बनते जा रहे हैं। भारत सहित कई देशों में पेपर बैग निर्माण का एक बड़ा उद्योग खड़ा हो रहा है, जो न केवल हरित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रहा है बल्कि रोजगार भी पैदा कर रहा है। आज विभिन्न स्टार्टअप और नवाचारों के माध्यम से बायोडिग्रेडेबल विकल्पों का निर्माण हो रहा है। भारत में डीआरडीओ ने कुछ निजी संस्थानों के साथ मिलकर प्लास्टिक के स्थान पर खाद्य-ग्रेड पौधों से बनने वाले बैग विकसित किए हैं, जो केवल 90 दिनों में स्वयं नष्ट हो जाते हैं। इन बैगों का डिजाइन इस तरह किया गया है कि ये न केवल उपयोगी हैं बल्कि जानवरों के लिए भी सुरक्षित हैं। इसी प्रकार, कनाडा, इजरायल, डेनमार्क जैसे देशों में घास, ताड़ के पत्ते, पराली, कपास और चुकंदर की खोई से जैव-प्लास्टिक तथा बायोपैकिंग सामग्री का निर्माण हो रहा है। यह सामग्री सस्ती, टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल होती है तथा इस्तेमाल के बाद कंपोस्ट बन जाती है।

भारत में भी कई स्टार्टअप केले और बड़े पत्तों से खाद्य पैकेजिंग का विकास कर रहे हैं। यह पारंपरिक भारतीय ज्ञान का पुनरुद्धार भी है, जहां पहले पत्तलों और दोने का चलन था। इन प्राकृतिक सधनों से बनी पैकेजिंग सामग्री न केवल पूर्णतः जैविक होती है बल्कि स्थानीय किसानों और हस्तशिल्पियों के लिए एक आय का स्रोत भी बनती है। वहीं दूसरी ओर, प्लास्टिक की थैलियों का स्वास्थ्य पर भी गंभीर प्रभाव पड़ता है। जब हम प्लास्टिक में पैक खाद्य सामग्री का सेवन करते हैं तो उसमें मौजूद हानिकारक रसायन हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। अध्ययन बताते हैं कि प्लास्टिक पैकेजिंग में मौजूद बिसफेनॉल-ए (बीपीए) और फ्थेलेट्स जैसे रसायन गैस, हार्मोन असंतुलन, प्रजनन संबंधी समस्याओं, पेट

की टीकाकरण दर और स्कूली शिक्षा के आँकड़े भी निम्न हैं। आदिवासी बहुत जितों में लगभग 40 प्रतिशत से अधिक बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित पाए गए हैं।

साथ ही, पर्यावरणीय दोहन और औद्योगिक विस्तार ने आदिवासियों को सबसे अधिक प्रभावित किया है। खनन, बाँध, और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं ने लाखों आदिवासी परिवारों को उनके पेतुक्त गाँवों से विस्थापित किया है। वर्ष 2006 में लागू वन अधिकार अधिनियम के तहत आदिवासियों को उनकी जमीन और जंगल पर अधिकार देने का वादा किया गया था, लेकिन 2024 तक लगभग 12 लाख परिवार ऐसे हैं जिनका मामला अब भी लंबित है। जिनके लिए जंगल जीवन का पर्याय था, वे आज कागजी युद्ध में उलझ कर रह गए हैं। शहरों में भी आदिवासी परिवार बेहतर जीवन नहीं पा सके हैं। वे छोटे-मोटे कामों में लग गए हैं, लेकिन उनकी सांस्कृतिक पहचान, भाषा और परंपराएँ शहर की दीवारों में दबती जा रही हैं। स्त्रियाँ घरेलू कामगार बन गई हैं। उनकी परंपरा, कला, ज्ञान और प्राकृतिक जुड़ाव को न तो शिक्षा व्यवस्था समझ पाई है, न शासन की योजनाएं।

आज भी भारत के कई हिस्सों में जनसंख्या नियंत्रण एक वर्जित विषय है। पुरुष नसबंदी को लेकर सामाजिक झिझक अब भी बहुत प्रबल है। स्थायी गर्भनिरोध के लगभग 90 प्रतिशत उपाय महिलाओं पर ही लागू होते हैं। यह केवल स्वास्थ्य या व्यवस्था की नहीं, बल्कि सामाजिक मानसिकता की समस्या है। महिलाओं को आज भी शिक्षा, रोजगार और निर्णय प्रक्रिया में बराबरी नहीं मिलती। देश में श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी मात्र 25 प्रतिशत है। घरेलू कार्य को अब भी ‘काम’ नहीं माना जाता। निर्णय लेने वाले मंचों पर महिलाओं की संख्या नागण्य है। शिक्षा की दर भले ही बढ़ी

विश्व पेपर बैग दिवस पर विशेष

इस गंभीर समस्या का एक सशक्त समाधान है ‘पेपर बैग’। पेपर बैग शत-प्रतिशत बायोडिग्रेडेबल होते हैं और कुछ ही हफ्तों में स्वयं तो समुद्री जीवों के लिए खतरा हैं, न ही भूजल या वायु प्रदूषण के कारक। पेपर बैग न केवल पर्यावरण-अनुकूल हैं बल्कि आज एक बड़ा आर्थिक अवसर भी बनते जा रहे हैं। भारत सहित कई देशों में पेपर बैग निर्माण का एक बड़ा उद्योग खड़ा हो रहा है, जो न केवल हरित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रहा है बल्कि रोजगार भी पैदा कर रहा है। आज विभिन्न स्टार्टअप और नवाचारों के माध्यम से बायोडिग्रेडेबल विकल्पों का निर्माण हो रहा है। भारत में डीआरडीओ ने कुछ निजी संस्थानों के साथ मिलकर प्लास्टिक के स्थान पर खाद्य-ग्रेड पौधों से बनने वाले बैग विकसित किए हैं, जो केवल 90 दिनों में स्वयं नष्ट हो जाते हैं। इन बैगों का डिजाइन इस तरह किया गया है कि ये न केवल उपयोगी हैं बल्कि जानवरों के लिए भी सुरक्षित हैं। इसी प्रकार, कनाडा, इजरायल, डेनमार्क जैसे देशों में घास, ताड़ के पत्ते, पराली, कपास और चुकंदर की खोई से जैव-प्लास्टिक तथा बायोपैकिंग सामग्री का निर्माण हो रहा है। यह सामग्री सस्ती, टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल होती है तथा इस्तेमाल के बाद कंपोस्ट बन जाती है।

भारत में भी कई स्टार्टअप केले और बड़े पत्तों से खाद्य पैकेजिंग का विकास कर रहे हैं। यह पारंपरिक भारतीय ज्ञान का पुनरुद्धार भी है, जहां पहले पत्तलों और दोने का चलन था। इन प्राकृतिक सधनों से बनी पैकेजिंग सामग्री न केवल पूर्णतः जैविक होती है बल्कि स्थानीय किसानों और हस्तशिल्पियों के लिए एक आय का स्रोत भी बनती है। वहीं दूसरी ओर, प्लास्टिक की थैलियों का स्वास्थ्य पर भी गंभीर प्रभाव पड़ता है। जब हम प्लास्टिक में पैक खाद्य सामग्री का सेवन करते हैं तो उसमें मौजूद हानिकारक रसायन हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। अध्ययन बताते हैं कि प्लास्टिक पैकेजिंग में मौजूद बिसफेनॉल-ए (बीपीए) और फ्थेलेट्स जैसे रसायन गैस, हार्मोन असंतुलन, प्रजनन संबंधी समस्याओं, पेट

की बीमारियों और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। यह खतरा विशेषकर बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों के लिए और भी अधिक है। भारत की स्थिति को देखें तो पॉलीथीन की थैलियों ने न केवल शहरी इलाकों की साफ-सफाई व्यवस्था को अस्त-व्यस्त किया है, बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी यह संकट गहराता जा रहा है। गांवों की गलियों से लेकर खेतों तक प्लास्टिक के टुकड़े बिखरे दिखाई देते हैं, जो मवेशियों द्वारा निगले जा रहे हैं और अंततः उनकी मृत्यु का कारण बन रहे हैं। विभिन्न पशु चिकित्सकीय अध्ययन बताते हैं कि हर साल हजारों गायें और भैंसें प्लास्टिक खाने के कारण मर जाती हैं।



मध्य प्रदेश के भौगोलिक गठन को लेकर निराश होता था. लगता था कि देश का हृदयप्रदेश कहलाने वाले मध्यप्रदेश की कोई एक भाषा, एक संस्कृति नहीं है. यहीं तक कि दो दशक पहले मध्यप्रदेश से अलग हुए छत्तीसगढ़ की भाषा छत्तीसगढ़ी है. लेकिन आज लगा रहा है कि मेरा मध्यप्रदेश समुच्च में अनुपम है. अलग है और एक धड़कते दिल की तरह वह भारत का प्रतिनिधि प्रदेश है. यहीं भाषा और संस्कृति को लेकर कोई विवाद नहीं है. वह बाँहें पसारे खुले मन से सबका स्वागत कर रहा है. यह प्रदेश भावभूमि है. यहीं देश के सभी प्रदेशों के भाषा-भाषी निवास करते हैं. उनकी संस्कृति और संस्कार को मध्यप्रदेश के रहने वाले स्वागत करते हैं. सच कहा जाए तो देश दिल मध्यप्रदेश भाषा और संस्कृति का राजदूत है. आज जब भाषा विवाद चरम पर है तब मध्यप्रदेश मुस्करा रहा है. शायद वह कह रहा है कि आओ, मुझसे सीखो कि भारत की बहुभाषी और संस्कृति को कैसे सम्मान दिया जाता है. पंडित नेहरू ने कभी मध्यप्रदेश को बेडौल प्रदेश कहा था लेकिन इसी बेडौल भू-भाग वाला मध्यप्रदेश भारत का आदर्श प्रदेश के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहा है.

मध्यप्रदेश का मुआयना करें तो आपको कई रीजन मिलेंगे. इनमें मालवा, महाकाशल, विन्ध्य, बुंदेलखंड, चंबल और कभी छत्तीसगढ़ भी इसका हिस्सा हुआ करता था. अपनी स्थापना के सात दशक बाद भी कभी यहीं भाषा विवाद सुलगा नहीं और ना ही संस्कृति को लेकर कोई विवाद हुआ जाता है. बहुभाषी साहित्य की जितना बड़ा मंच मध्यप्रदेश में मिला, वह कहीं और नहीं. भारत के इस प्रतिनिधि प्रदेश में हर प्रदेश का स्वागत है. भरोसा ना हो तो एक बार भारत भवन के आयोजन का कैलेंडर उठा कर देखा लीजिए, प्रतिवर्ष देश के सभी राज्यों की कलाओं का प्रदर्शन होता है, भागीदारी होती है. विविध भाषाओं के साहित्य पर चर्चा होती है. यही नहीं, मध्यप्रदेश की साहित्यिक सांस्कृतिक संगठन में हर

हो, परंतु सोच अब भी उस स्तर पर नहीं पहुँची है जहाँ हम एक समान समाज की कल्पना कर सकें। महिलाएं अभी भी निर्णय प्रक्रिया में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं रखतीं। एक ‘कामकाजी महिला’ आज भी समाज में असामान्य घटना के रूप में देखी जाती है, जबकि यह उसकी स्वतंत्रता का प्रतीक होना चाहिए। यह स्पष्ट है कि कोई एक योजना, नीति या कानून इस संकट का समाधान नहीं कर सकता। आवश्यकता है – सोच के पुनर्निर्माण की, उस चेतना की जो हर नागरिक को समान अवसर, गरिमा और सम्मान के साथ देखे। परिवार नियोजन को स्वास्थ्य का हिस्सा नहीं, मानव अधिकार के रूप में देखना होगा। महिलाओं को केवल लाभार्थी नहीं, नीति-निर्माता की भूमिका में लाना होगा। आदिवासी क्षेत्रों में योजनाओं को उनके सांस्कृतिक और भौगोलिक संदर्भ में डिजाइन करना होगा। शिक्षा केवल साक्षरता नहीं, बल्कि वैचारिक आजादी का माध्यम बननी चाहिए।

अगर हम हर स्त्री, हर बच्चे, हर आदिवासी, हर नागरिक के अधिकार और गरिमा की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो यह बढ़ती जनसंख्या हमारे लिए एक अवसर नहीं, बल्कि एक बोझ बनती जाएगी। हैं। यह दिन सिरफ आँकड़ों को देखने या सरकारों की योजनाओं की समीक्षा का अवसर नहीं है, बल्कि एक ज़रूरत है – सामूहिक आत्मस्थेन की ओर यह जानने की कि क्या हम एक जीवंत, विवेकशील समाज की ओर बढ़ रहे हैं या सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनते जा रहे हैं। जब तक समाज का सबसे कमजोर वर्ग सशक्त नहीं होगा, तब तक कोई भी जनसंख्या लाभ नहीं दे सकती। सोच को बदलना सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम है। अब समय है कि हम सोचें – हम कहाँ जा रहे हैं? और उससे भी ज़रूरी यह है कि हम यह तय करें – हमें कहाँ जाना चाहिए।

विश्व पेपर बैग दिवस पर विशेष

इस गंभीर समस्या का एक सशक्त समाधान है ‘पेपर बैग’। पेपर बैग शत-प्रतिशत बायोडिग्रेडेबल होते हैं और कुछ ही हफ्तों में स्वयं तो समुद्री जीवों के लिए खतरा हैं, न ही भूजल या वायु प्रदूषण के कारक। पेपर बैग न केवल पर्यावरण-अनुकूल हैं बल्कि आज एक बड़ा आर्थिक अवसर भी बनते जा रहे हैं। भारत सहित कई देशों में पेपर बैग निर्माण का एक बड़ा उद्योग खड़ा हो रहा है, जो न केवल हरित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रहा है बल्कि रोजगार भी पैदा कर रहा है। आज विभिन्न स्टार्टअप और नवाचारों के माध्यम से बायोडिग्रेडेबल विकल्पों का निर्माण हो रहा है। भारत में डीआरडीओ ने कुछ निजी संस्थानों के साथ मिलकर प्लास्टिक के स्थान पर खाद्य-ग्रेड पौधों से बनने वाले बैग विकसित किए हैं, जो केवल 90 दिनों में स्वयं नष्ट हो जाते हैं। इन बैगों का डिजाइन इस तरह किया गया है कि ये न केवल उपयोगी हैं बल्कि जानवरों के लिए भी सुरक्षित हैं। इसी प्रकार, कनाडा, इजरायल, डेनमार्क जैसे देशों में घास, ताड़ के पत्ते, पराली, कपास और चुकंदर की खोई से जैव-प्लास्टिक तथा बायोपैकिंग सामग्री का निर्माण हो रहा है। यह सामग्री सस्ती, टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल होती है तथा इस्तेमाल के बाद कंपोस्ट बन जाती है।

दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ शहरी क्षेत्रों में अब ऐसे स्टोर खुल रहे हैं, जहां ग्राहकों को थैला या डिब्बा लाना आवश्यक होता है। यह न केवल पर्यावरणीय दृष्टि से लाभकारी है बल्कि उपभोक्ताओं को अपने कचरे की मात्रा का भी आकलन करने की आदत डालता है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु संकट, जैव विविधता हानि और पर्यावरणीय विषाक्तता जैसी चुनौतियों का सामना कर रही है, तब एक साधारण कागज का थैला इन समस्याओं से लड़ने में एक बड़ा हथियार बन सकता है। यह न केवल प्लास्टिक के विकल्प के रूप में उपयोगी है बल्कि एक ऐसी सोच का प्रतीक भी है, जो प्रकृति के साथ सह-अस्तित्व की ओर बढ़ रही है। इसलिए सरकारों की भी चाहिए कि वे पेपर बैग उद्योग को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक सुविधाएं, प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता प्रदान करें। छोटे स्तर पर पेपर बैग बनाने वाले कारीगरों और महिला समूहों को प्रोत्साहित करना भी एक अच्छा कदम है। साथ ही प्लास्टिक के इस्तेमाल पर जुर्माने और सख्ती के साथ पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। सही मायनों में विश्व पेपर बैग दिवस का उद्देश्य एक चेतावनी है कि यदि हम अभी भी नहीं संभले तो पृथ्वी पर जीवन का भविष्य संकट में पड़ जाएगा। यह एक आह्वान है कि हम अपनी आदतें बदलें, अपने उपभोग की प्रवृत्तियाँ पर लगाम लगाएं और एक ऐसे समाज की रचना करें, जहां विकास और पर्यावरण एकलव्य में हों। जब हम एक पेपर बैग को थामते हैं, तब हम केवल सामान नहीं उठाते बल्कि हम एक जिम्मेदारी उठाते हैं धरती को बचाने की।

विश्व पेपर बैग दिवस पर विशेष

भाषा को स्थान दिया गया है. मध्यप्रदेश संस्कृति परिषद में मराठी, सिंधी, पंजाबी, भोजपुरी अकादमी है तो मध्यप्रदेश ने मग की कि हम सिंधी की शिक्षा देगे तो हाल ही में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल में इस पाठ्यक्रम को अनुमति मिल गई और जल्द ही औपचारिक शिक्षा भी शुरू हो जाएगी. देश के हृदयप्रदेश का हृदय हर प्रदेश के लिए धड़कता है और यही कारण है कि मध्यप्रदेश राजभवन में एक-एक कर विभिन्न राज्यों का स्थापना दिवस उत्सव मनाया जाता है.

भारत देश बहुभाषी संस्कृति और साहित्य का देश है. भाषा और बोली की यह खूबसूरती है कि हम सब मिलकर वस्तरों दुनिया गढ़ते हैं. गर्व के साथ मैं कह सकता हूँ कि मध्यप्रदेश भारत की इस छवि का प्रतिनिधि प्रदेश है. राजदूत हो जो शांति, समन्वय और सद्भाव के संदेश को भेजता है. राज्य सरकार के अध्यक्ष कोशिश से मध्यप्रदेश में लगातार फ़िल्मों, टीवी सीरियल्स और ओटीटी प्लेटफ़ार्म के लिए निर्माण हो रहा है. इमदाद और मदद दोनों फ़िल्ममेकर्स को मिल रहा है लेकिन परदे पर कहीं एक पंक्ति नहीं दिखता ‘धन्यवाद मध्यप्रदेश’, बावजूद इसके हम उनका हमेशा से स्वागत करने तिलक रोरी लिए खड़े होते हैं. वर्तमान सरकार तो पीले चावल लेकर प्रदेश-दर-प्रदेश जा रही है कि आएँ, हमारे प्रदेश में उद्योग लगाइए, मध्यप्रदेश इतना कर रहा है लेकिन सवाल है कि क्या मध्यप्रदेश जैसी सुंदर, सुखद पहल को देख कर रहा है? क्या हम सब भारत माता के लाल नहीं हैं? इस पर विचार करना जरूरी हो जाता है. देश में छिड़ा भाषा विवाद नया नहीं है. समय-समय पर यह विवाद होता रहा है. इसमें सबसे अहम बात यह है कि भाषा का विरोध अर्थात हिन्दी का विरोध. हर प्रदेश की एक भाषा है और उसका सम्मान किया जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है. इसी बहुभाषी संस्कृति से भारत को विश्व में अलग पहचान है.

भाषा विवाद के संघट बड़े हैं. वह ना केवल राष्ट्रीय एकता और संघर्षभा को संकट में डालता है बल्कि रोजी-रोजगार पर भी असर होता है. इस विवाद में एक उपाय यह भी हो सकता है कि आक्रमक होने के बजाय भाषा प्रशिक्षण केन्द्र हर राज्य में आरंभ कर दे. जिन्हें यह भाषा नहीं आती, उन्हें सीखने और समझने का अवसर दे. इससे शायद कोई रास्ता सुंदर निकल आए. रास्ता ना सही, एक पगडंडी तो मिल ही जाएगी. वैसे भी हिन्दी की खूबसूरती देखिए जिसका आप विरोध कर रहे हैं, वही आपको एक कर रही है.

केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर, विधायक नीना वर्मा, जिलाध्यक्ष निलेश भारती ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर साधु-संतों, गुरुजनों का किया सम्मान

भाजपा जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में जिले के प्रत्येक मंडलों में गुरुओं का किया गया सम्मान

धारा। श्री गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय, प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर जिले के प्रमुख धार्मिक स्थल पर केंद्रीय राज्य मंत्री एवं सांसद सावित्री ठाकुर, विधायक नीना विक्रम वर्मा भाजपा जिलाध्यक्ष महंत निलेश भारती ने शाल श्रीफल भेंट कर साधु संतों गुरुओं का किया सम्मान। मंदिर पहुंचकर भगवान शिव की पूजन अर्चना करते हुए देश के लिए सुख और समृद्धि की कामना की। केंद्रीय मंत्री एवं सांसद सावित्री ठाकुर ने माण्डव श्रीराम मंदिर पर महामंडलेश्वर डॉ. नरसिंहदास जी महाराज तथा बदनावर विधानसभा क्षेत्र ग्राम छाजन आश्रम में संत पूजन किया। भाजपा जिलाध्यक्ष महंत निलेश भारती और विधायक नीना विक्रम वर्मा ने धार स्थित श्री नित्यानंद आश्रम में अवधूत पूज्य गुरुदेव नित्यानंद बापजी के दर्शन कर पूजन किया।

गुरु ही हमें मार्ग दिखाते हैं: महंत निलेश भारती

भाजपा जिलाध्यक्ष महंत निलेश भारती ने कहा कि गुरु पूर्णिमा का बहुत बड़ा महत्व मानव के जीवन में होता है। गुरु हमें मार्ग दिखाकर सफलता की ओर ले जाते है हर व्यक्ति को



अपने जीवन में गुरु बनाकर उनसे आशीर्वाद ग्रहण करते रहें। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी संजय शर्मा ने बताया कि श्री गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जिले के सभी मंडलों के प्रमुख धार्मिक स्थानों पर भाजपा नेता व जनप्रतिनिधियों ने पहुंचकर गुरुओं और साधु, संतों का सम्मान किया। कार्यक्रम जिला संयोजक भाजपा जिला उपाध्यक्ष

विश्वास पांडे, खेल प्रकोष्ठ संयोजक लाखन सिंह नवासा ने खेल प्राधिकरण जेतपुरा में खेल प्रशिक्षकों का सम्मान किया। इसी प्रकार डॉ शरद विजयवर्गीय दिलीप पटोदिया जगदीश जाट पूनमचंद फकीरा दीपक फेमस सहित अनेक भाजपा नेता व पदाधिकारियों ने विभिन्न धार्मिक गुरु स्थानों पर साधु संतों गुरुओं का सम्मान किया।

मप्र विद्युत मंडल पेंशनर्स एसोसिएशन की मासिक बैठक आज

बैतूल। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल पेंशनर्स एसोसिएशन की मासिक बैठक आज 12 जुलाई को दोपहर 12 बजे लिंक रोड स्थित कैपेन हाउस में आयोजित की गई है।एसोसिएशन के कार्यकारी अध्यक्ष बीपी धामोढ़े ने बताया कि हाल ही में जबलपुर स्थित कोकिला रिसॉर्ट में 24 जून को आयोजित प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी इस बैठक में दी जाएगी। बैठक में महंगाई राहत से संबंधित धारा 49(6) तथा पेंशन एक्टों गारंटी के संबंध में शासन से की जा रही मांग पर चर्चा होगी। इस संदर्भ में एसोसिएशन के अध्यक्ष एस.के. जयसवाल एवं अन्य पदाधिकारी 20 जुलाई को ग्वालियर में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर से भेंट कर विषय की गंभीरता से अवगत कराएँ। इसके अतिरिक्त पेंशन कम्प्यूटेशन की अवधि को लेकर फैली भ्रांतियों, इंदौर उच्च न्यायालय के निर्णय की वास्तविक स्थिति, 79 वर्ष की आयु में 20 प्रतिशत पेंशन वृद्धि, आठवें वेतन आयोग में पेंशनर्स को संभावित सुविधाएं, लॉबित भुगतान, कैशलेस चिकित्सा बीमा योजना की प्रगति तथा संगठन को मजबूत करने के लिए सदस्यों से प्राप्त सुझावों पर भी विस्तार से विचार किया जाएगा। श्री धामोढ़े ने सभी सदस्यों से बैठक में उपस्थित होने का आग्रह किया है।

रोजगार मेले में 68 अभ्यर्थियों का चयन

बैतूल। जिला रोजगार कार्यालय, आईटीआई, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में युवा संगम के तहत शुक्रवार को जिला स्तरीय रोजगार, स्वरोजगार एवं अंतिमसशिप मेले का आयोजन शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था बैतूल में किया गया। जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि रोजगार मेले में कुल 158 आवेदकों ने पंजीजन कारया था। जिसमें 07 कर्मनिर्णयों के द्वारा 68 आवेदकों का प्राथमिक रूप से चयन कर 04 को लेटर ऑफ इंटेंट प्रदान किए गए। रोजगार मेले के साथ ही आईटीआई में स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वास्थ्य परिक्षण शिविर भी आयोजित किया गया। स्वास्थ्य शिविर में 92 मरीजों की स्वास्थ्य जांच की गई, जिसमें 36 जांच सिकलसेल की गई।

विश्व जनसंख्या दिवस पर जागरूकता रथ को दिखाई हरी झंडी

●स्वास्थ्य संस्थानों में चलेगा विशेष प्रचार अभियान, परिवार नियोजन पर रहेगा फोकस



बैतूल। विकास खण्ड चिचोली में विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर जनसंख्या स्थिरीकरण माह का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर विकास खण्ड स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया और जनजागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। मुख्य खण्ड चिकित्सा अधिकारी चिचोली डॉ राजेश अतुलकर ने बताया कि प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है और इसके साथ ही 11 जुलाई से 11 अगस्त तक जनसंख्या स्थिरीकरण माह के रूप में अभियान संचालित किया जाता है। इस वर्ष भी यह अभियान विकास खण्ड चिचोली के सभी स्वास्थ्य संस्थानों और जनसमुदाय स्तर पर आयोजित किया जाएगा। इसमें परिवार नियोजन के महत्व का प्रचार-प्रसार कर लोगों को जागरूक किया जाएगा और आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। चिकित्सालय चिचोली में आयोजित इस कार्यक्रम में डॉ राजेश अतुलकर के उद्देशे, बीपीएम एकनाथ ठाकुर, बीसीएम विनीत आर्य, एमटीएस पंकज डोंगरे सहित कार्यालयीन और मैदानी कर्मचारियों ने सहभागिता की।



जनपद झाड़-फूंक में जाती है जानें, सर्पदंश से निपटने जिला प्रशासन कर रहा जागरूक

सर्पदंश- पिछले 15 माह में सर्पदंश के 521 लोग शिकार, लगभग 50 की मौत

संजय द्विवेदी, बैतूल। हर साल मानसून में सर्पदंश के मामले बढ़ते हैं। कई लोगों की मौत भी हो जाती है। इसके पीछे बड़ा कारण यह है कि सर्पदंश की घटना के बाद लोग उपचार में लापरवाही या लेटलतपीी करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी सांप काटने पर झाड़-फूंक का ही सहारा लिया जाता है। अगर जिले की बात करें, तो वर्ष 2024-25 में सर्पदंश के 471 मामले सामने आए थे। वहीं 2025-26 में अब तक करीब 41 मामले आ चुके हैं। चिकित्सकों की मानें, तो लोगों द्वारा सावधानी नहीं बरते जाने के कारण बारिश में सर्पदंश की घटनाएं ज्यादा होती हैं। डॉक्टरों के मुताबिक कुछ ही प्रजापति के सांप है जिसके काटने से मौत होती है। खासकर कोबरा, रसेल वाइपर और करैत प्रजाति के सांपों काटने से लोगों की मौत होती है। अगर सर्पदंश के तुरंत बाद समय पर इलाज के लिए मरीज को अस्पताल ले जाये, तो उनकी जान बच सकती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी लोग झाड़-फूंक कराते है और इसके बाद इलाज में देरी के कारण लोगों की जान तक चली जाती है।

15 माह में 521 मामले, 50 की लगभग मौत: मौसम बदलने के साथ सर्पदंश की घटनाओं के मामले आना शुरू हो गए हैं। हर साल कई लोग सर्पदंश का शिकार होते हैं। बीते 15 माह में जिले में

सर्पदंश के 521 मामले जिला अस्पताल में पहुंचे हैं। इससे हर साल 40 से 50 लोगों की मौत हो रही है। सर्पदंश से पीड़ित को बचाने के लिए इस वर्ष बारिश के पूर्व ही प्रत्येक विकासखंड में इसकी व्यवस्था करा दी गई है। लगभग 25 से 30 वायल एंटी स्रेक वेनम जिले के हर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उपलब्ध कराए गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि एंटी स्रेक वेनम की सुविधा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में भी उपलब्ध होनी चाहिए, ताकि पीड़ितों को लंबी दूरी तय न करनी पड़े। असमय किसी को भी अपनी जान सपदंश के कारण न गंवाना पड़े।

सबसे अधिक ग्रामीण क्षेत्र में सर्पदंश की घटनाएं: जिले की अधिकांश आबादी ग्रामीण अंचलों में बसी है। इन इलाकों में जहरीले जीव-जंतुओं का खतरा अधिक होता है। यही कारण है कि सर्पदंश



से मरने वाले ग्रामीण क्षेत्र के लोग अधिक है। चिकित्सक भी इन मौतों का कारण जागरूकता का अभाव बताते हैं। इसलिए समय पर इलाज जरूरी है, लेकिन ग्रामीण उपचार न कराते हुए पहले झाड़-फूंक में ही लगे रहते हैं। इस दौरान जहर पूरे शरीर में फैल जाता है और मौत हो जाती है। जानकार बताते हैं कि कई बार मौत का कारण जहर नहीं, बल्कि घबराहट भी होती है। डर से बीपी बढ़ता है, हार्ट अटैक या स्ट्रोक आने की आशंका होती है। कई मामले ऐसे भी आए, जहां सांप जहरीला नहीं था, लेकिन व्यक्ति की मौत कार्डियक अरेस्ट से हो गई।

जिला प्रशासन चला रहा जागरूकता अभियान : जिले में सर्पदंश की बढ़ती घटनाओं और इससे होने वाली मौतों को रोकने जिला प्रशासन को जागरूकता अभियान चलाना पड़ रहा है। बताया गया कि सर्पदंश के बाद शांत रहें

और घबराएं नहीं, घबराने से हृदय की गति बढ़ जाती है, जिससे जहर का फैलाव शरीर में तेजी से हो सकता है। पीड़ित व्यक्ति का सिर ऊंचा रखकर लिटाएं। घाव को साफ पानी एवं साबुन से धो लें। घाव से खून का रिसाव होने दें। घाव पर ढीली व साफ पट्टी रखें। पीड़ित व्यक्ति को जितनी जल्दी हो सके, नजदीकी स्वास्थ्य संस्था में ले जाकर उपचार करवाएं। यदि संभव हो तो सांप की पहचान करने की कोशिश करें। सांप को पकड़ने या मारने का प्रयास न करें।

इनका कहना है -

जिला अस्पताल में एंटी स्रेक वेनम पर्याप्त उपलब्ध है, क्योंकि जिले भर के सर्पदंश से पीड़ित सबसे ज्यादा मरीज जिला अस्पताल में ही पहुंचते हैं। इसलिए पर्याप्त स्टॉक रखा जाता है। सामुदायिक केंद्रों पर भी एंटी स्रेक वेनम दिए गए हैं।

- डॉ जगदीश घोरे, सिविल सर्जन जिला अस्पताल बैतूल

नगर पालिका द्वारा पहले एक प्रशिक्षित प्राइवेट व्यक्ति, जो सांप पकड़ने में माहिर था, को अनुबंधित किया गया था, परंतु उसके बीमार पड़ जाने के बाद हमारे द्वारा नागरिकों के घरों में निकलने वाले सांप आदि को पकड़ने हेतु फॉरेस्ट विभाग की सहायता से ही यह कार्य किया जाता है।

- सतीश मटसेनीया, सीएमओ, नगर पालिका बैतूल

वर्षा ऋतु में कोई भी जन-धन की हानि न हो, अधिकारी अलर्ट रहें : संभागायुक्त

संभागायुक्त की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित

बैतूल। वर्षा ऋतु के दौरान सभी एसडीएम, जनपद सीईओ, सीएमओ और सम्बन्धी विभागों के अधिकारी सतर्क रहें। सुरक्षा के सभी पूर्व आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। सार्वजनिक इमारतों, स्कूल भवनों, आंगनवाड़ियों, स्वास्थ्य केन्द्रों पर सतत नजर बनाए रखें। जर्जर भवनों को तत्काल डिस्मेंटल कराएं। किसी भी प्रकार की जनहानि और धन हानि न हो यह सुनिश्चित किया जाए। यह निर्देश संभागायुक्त नर्मदापुरम श्री के जी तिवारी ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट बैतूल में आयोजित बैठक में अधिकारियों को दिए। बैठक में कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी, वन मंडल अधिकारी उत्तर नवीन गर्ग, वन मंडल अधिकारी वरुण यादव, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अश्वत जैन, प्रशिक्षु आईएफएस सुंदर निवेदन, उपायुक्त नर्मदापुरम भी गणेश, अपर कलेक्टर श्री राजीव नंदन श्रीवास्तव सहित जिले के सभी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित हैं। उन्होंने सभी अधिकारियों से कहा कि जनसामान्य के कार्यों को पूरी जिम्मेदारी और संवेदनशीलता से किया जाए। जनपद सीईओ, सीएमओ नगरपालिक , सडक़ विभाग सतत अपने क्षेत्रों का भ्रमण करते रहे और सुनिश्चित करें कि सडकों को स्थित अच्छी रहे। सडकों पर गड्डे होने की शिकायतों का त्वरित निराकरण कराएं। इसी प्रकार नाली के ब्लॉकेज, पेयजल, बिजली, जलभराव की समस्याएं आने कर उनका तत्परता से समाधान कराएं। संभागायुक्त श्री तिवारी ने निर्देशित किया कि सभी एसडीएम अपने क्षेत्र में संपूर्ण व्यवस्थाओं के लिए जिम्मेदार हैं। विभागीय अधिकारियों से समन्वय और सहयोग से कार्य करना आपका प्रमुख उत्तरदायित्व है। इसी



प्रकार विकास से जुड़े कार्यों में भी एसडीएम लीडरशिप लें। अपने क्षेत्र में फीड बैक सिस्टम डेवलप करें। नकारात्मक खबरों पर त्वरित एक्शन लिया जाए। रोस्टर तय कर विभागों के कार्यों का निरीक्षण किया जाए। उन्होंने सभी सीएमओ,जनपद सीईओ और बीएमओ से वर्षा की तैयारियों की जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

कोई भी ऑफलाइन दर्ज न हो राजस्व प्रकरण

वन खंड व्यवस्थापन के प्रकरणों की अनुविभागवार समीक्षा कर संभागायुक्त श्री तिवारी ने कहा कि प्रकरणों में आवश्यक बिंदुओं का पालन कर उन्हें दर्ज कराएं। उन्होंने सभी राजस्व अधिकारियों से ऑफलाइन दर्ज प्रकरणों के बारे में जानकारी और निर्देशित किया कि कोई भी प्रकरण ऑफलाइन दर्ज नहीं किया जाए। ऑफलाइन दर्ज पाए जाने पर संबंधित एसडीएम के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी। एसडीएम और एसडीओ फॉरेस्ट की जानकारी और समन्वय में कमी न हो। उन्होंने स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और अन्य संबंधित विभागों को वन विस्थापन के प्रकरणों का एसडीओ फॉरेस्ट से समन्वय कर निराकरण कराएं। सभी राजस्व अधिकारी

अपने क्षेत्र में अभियान चलाकर जाति प्रमाण पत्र बनाए जाएं।

निजी स्कूल वाहनों की करें जांच

उन्होंने निर्देश दिए कि सभी एसडीएम सुनिश्चित करें कि ज्ञात और अज्ञात वाहन से होने वाली दुर्घटना में राहत के प्रकरण लंबित न रहें। अपने क्षेत्र के थाने के साथ राहत प्रकरणों की सतत समीक्षा करें। उन्होंने कहा कि सडक़ सुरक्षा के दृष्टिगत अपने क्षेत्र में ब्लैक स्पॉट का चिन्हंकन कर वहां सुरक्षा के सभी उपाय सुनिश्चित किए जाएं। निजी बस वाहनों की निरीक्षण भी किया जाए। निजी स्कूल बस वाहन की फिटनेस, वाहन चालक सहित अन्य आवश्यक प्रमाणित जानकारी ली जाए। अवैध उत्खनन एवं परिवहन के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही कराएं।प्रदूषण के दृष्टि से पॉल्यूशन कंट्रोल द्वारा औद्योगिक इकाइयों की भी निष्पक्ष रूप से जांच की जाए। संभागायुक्त श्री तिवारी ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास को निर्देश दिए कि अपने क्षेत्र में बाल मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में कमी लाने के लिए गंभीरता से कार्य करें।

अपने क्षेत्र में अभियान चलाकर जाति प्रमाण पत्र बनाए जाएं।

निजी स्कूल वाहनों की करें जांच

उन्होंने निर्देश दिए कि सभी एसडीएम सुनिश्चित करें कि ज्ञात और अज्ञात वाहन से होने वाली दुर्घटना में राहत के प्रकरण लंबित न रहें। अपने क्षेत्र के थाने के साथ राहत प्रकरणों की सतत समीक्षा करें। उन्होंने कहा कि सडक़ सुरक्षा के दृष्टिगत अपने क्षेत्र में ब्लैक स्पॉट का चिन्हंकन कर वहां सुरक्षा के सभी उपाय सुनिश्चित किए जाएं। निजी बस वाहनों की निरीक्षण भी किया जाए। निजी स्कूल बस वाहन की फिटनेस, वाहन चालक सहित अन्य आवश्यक प्रमाणित जानकारी ली जाए। अवैध उत्खनन एवं परिवहन के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही कराएं।प्रदूषण के दृष्टि से पॉल्यूशन कंट्रोल द्वारा औद्योगिक इकाइयों की भी निष्पक्ष रूप से जांच की जाए। संभागायुक्त श्री तिवारी ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास को निर्देश दिए कि अपने क्षेत्र में बाल मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में कमी लाने के लिए गंभीरता से कार्य करें।

इस युग के हम साक्षी हैं यह परम सौभाग्य : योगेश पंडाग्रे



बैतूल। शासकीय कन्या गंज के सभागार में मेरा युवा भारत बैतूल युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एक पेड़ मां के नाम अभियान का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम आमला विधायक डॉ योगेश पंडाग्रे, जिला पंचायत उपाध्यक्ष हंसराज धुर्वे, समाजसेवी ऋषिराज सिंह परिहार व प्राचार्य ललित लिल्होरे जिला युवा अधिकारी के आतिथ्य में और माय भारत की जिला अधिकारी श्रीमती सुष्मा गवली की अध्यक्षता में हुआ।

जिला अधिकारी सुष्मा गवली ने बताया कि युवा मंडल महिला मंडल समाज सेवा के सहयोग से यह अभियान निरंतर चला जाएगा जिससे कि अधिक से अधिक पौधों का रोपण हो सके इस क्षेत्र में हम सभी पहल कर रहे हैं। ऋषिराज सिंह परिहार ने कहा कि हम सभी का एक विशेष दायित्व बनता है कि हमें कहीं ना कहीं पर्यावरण संरक्षण को देखते हुए पौध रोपण करने की आवश्यकता है। जिला पंचायत उपाध्यक्ष ने कहा कि आने वाली पीढ़ी को शुद्ध पर्यावरण प्रदान कर सके इसके लिए अधिक से अधिक पौधे

लगाने होंगे। आमला विधायक डॉ.योगेश पंडाग्रे ने कहा कि हम भाग्यशाली है जो कि इस युग के साक्षी बन रहे है। भारत सरकार देश में एक पेड़ मां के नाम अभियान को चला रही है इस अभियान को हम जन-जन तक पहुंचाएं। डॉ.शंकर सातकर ने भी पर्यावरण पर अपने विचार रखे। डॉ.पंडाग्रे ने ग्लोबल वार्मिंग विषय पर स्कूल बच्चों से परिचर्चा की और सभी को सामूहिक तौर पर एक पेड़ मां के नाम की शपथ भी दिलाई गई। इस अवसर पर डॉ.शंकर सातकर ने बड़े विस्तार पूर्वक प्रकृति पर अपने विचार रखे। कार्यक्रम का संचालन धनंजय सिंह ठाकुर ने व अभार प्राचार्य ललित लिल्होरे ने आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर इस अवसर पर फिजी भाटिया, महेश गुजेल, रामनारायण शुक्ला, राधेलााल बनखेडे, हुकुमचंद कालभार, शुभम गोचर, राकेश मन्नायासे, शिवसागर सिंह, जीवन उच्चसरे, मलूकचन्द पवार, हेमन्त विश्वकर्मा, शैलेन्द शर्मा, गजेंद्र पवार, हिमांशु मालवीय शाहिद युवा मंडल महिला मंडल व शारदा समिति के पदाधिकारी सहित सदस्य उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने किया आवास अनुदान का वितरण, बैतूल के 130 हितग्राही लाभान्वित

चयनित पात्र हितग्राहियों को आवास स्वीकृति पत्रों का किया वितरण

बैतूल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित एमपी ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025 में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत प्रदेश के 60 हजार से अधिक हितग्राहियों को एक क्लिक के माध्यम से 1,513.53 करोड़ रुपये की अनुदान राशि का भी वितरण किया। इसी के अंतर्गत बैतूल जिले में भी कार्यक्रम का आयोजन नगर पालिका के बाल सभागार में किया गया। इस कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती पार्वती बाई बारस्कर, उपाध्यक्ष महेश राठौर, सभापति नितेश परिहार, वरिष्ठ पार्षद रघुनाथ लोखंडे, पार्षद श्रीमती सोमती धुर्वे, अशोक नागले, एवं मुख्य नगर



पालिका अधिकारी सतीश मत्सानिया उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान बैतूल नगर पालिका अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत चयनित पात्र हितग्राहियों को आवास स्वीकृति पत्रों का वितरण किया गया। इसके साथ ही बैतूल में निर्मित बारह आवासों में विधिवत गृह प्रवेश भी

संपन्न हुआ।उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत 130 पात्र हितग्राही है। बाल सभागार में आयोजित कार्यक्रम में इंदौर से हो रहे मुख्य आयोजन का सीधा प्रसारण भी किया गया, जिसे उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं हितग्राहियों ने देखा।

देश में गरीबों के लिए आवास और अन्न का प्रबंध करने वाले नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री : पार्षद शर्मा

आमला । देश में आजादी के लगभग 70 वर्षों के बाद गरीबों के आवास और अन्न के लिए पहली बार धरातल पर युद्ध स्तर पर काम होते देखा है, पहले हर गरीब का बस यही सपना होता था कि उसकी भी कभी पक्की छत होगी, और परिवार को पेट भर अन्न मिल पाएगा। गरीबों का ये सपना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साकार किया है, अब हर गरीब के पास अपना पक्का मकान और राशन भी फ़ी मिल रहा है, उक्त वक्तव्य वार्ड 5 के पार्षद राकेश शर्मा ने नगर पालिका सभा कक्ष में एमपी ग्रोथ कॉन्क्लेव सिटीज ऑफ़ टुमोरो के वर्चुअल कार्यक्रम में कहे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव के उद्घोषन को भी टीवी पर देखा, सुना गया इस मौके पर नगर पालिका के नवागत मुख्य नगरपालिका अधिकारी नितिन बिजवे का सभी पार्षदों ने फूल मालाओं से स्वागत किया और शहर के कार्यों में उनसे तेजी लाने की अपेक्षा भी की है। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष नितिया गाडरे ने अपने संबोधन में कहा कि आवास योजना के लाभार्थी शीघ्र अपने आवास के काम को गंभीरता पूर्ण करें, साथ ही ऐसे हितग्राही जो अभी तक इस योजना से वंचित रह गए हैं उन्हें भी सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना का लाभ लेना चाहिए।



